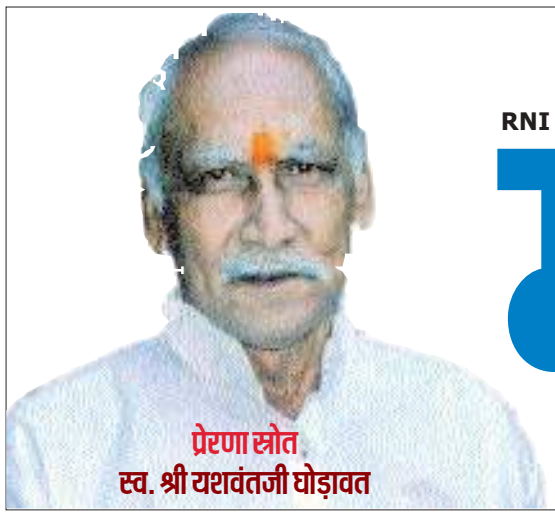

प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

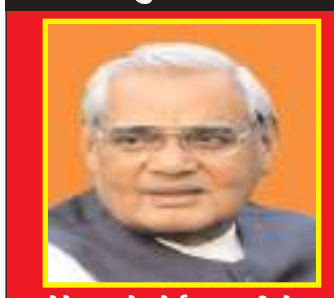

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता...
अटलबिहारी वाजपेयी

वर्ष-02, अंक -46 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 20 अगस्त 2020 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

भर्ती नियम अनुसार मिलना था सभी वर्गों को लाभ, लेकिन ताक में रख दिए गए सारे नियम कायदे

अंशकालीन पद पर लगी पत्नी को कलेक्टर दर पर लगा कर करवाया स्थाई, आदेश में पद तक का उल्लेख नहीं

सहायक आयुक्त द्वारा रसोइन के अटैचमेंट का आदेश

प्राचार्य द्वारा अधिकारी के अटैचमेंट को स्वयं समाप्त कर कार्यमुक्त करने का जारी आदेश

कन्या प्राचार्य द्वारा 1 जुलाई 2010 को जारी कलेक्टर दर पर रसोइन के पद पर कार्य करने की स्वीकृति हेतु सहायक आयुक्त को भेजे गए पत्र की प्रति

2 जुलाई 2010 को कार्य करने की अनुमति हेतु जारी आदेश की प्रति जिसमे पद का उल्लेख तक नही।

माही की गूंज, झाबुआ, संजय भटेवरा

आदिवासी विकास विभाग में पदस्थ एक बाबू के खेल के उजागर होते ही पूरे जिले में भर्ती के बड़े खेल की पोल खुलने की संभावना हो गई है। शासन ने भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर होने वाली नियुक्ति में सभी वर्गों को तय मापदंडों अनुसार अवसर देने का मौका दिया है, लेकिन जो नियुक्ति स्थानीय प्राचार्य और जिला अधिकारी के हाथों में है, वहां इस नियम का किसी प्रकार का कोई ध्यान नही रखा गया। वर्तमान में बीईओ ऑफिस में पदस्थ बाबू रामचंद्र अटकान के परिवार के सदस्यों की थोकबंद भर्ती से तय हो जाता है कि, सभी नियुक्तियों में केवल बाबू के परिवार के सदस्य होने का ध्यान रखा गया, जबकि अलग-अलग जगह हुई भर्ती में नियमानुसार एसटी, एसी, ओबीसी और जनरल वर्ग सहित महिला व पुरुष का ध्यान रख सभी को लाभ दिया जाना था, परन्तु नियम के विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति जारी नहीं की ओर एक ही परिवार को लाभ दिया गया। सम्भव है ऐसा केवल पेटलावद में ही नही बल्कि पेटलावद सहित जिले की अन्य संस्थाओं ने भी इस प्रकार से नियम विरुद्ध जाकर भर्ती की प्रक्रिया की गई होगी जिसकी निष्पक्ष रूप से व उच्चस्तरीय जॉच की जाए तो विभागीय सेटिंग के काले कारनामे उजागर हो सकते है।

बाबू ने पत्नी को अंशकालीन से कलेक्टर दर पर नियुक्त करवाकर बना दिया स्थाईकर्मी

बाबू रामचंद्र अटकान का जैसे ही पेटलावद से ट्रांसफर हुआ सबसे पहले बाबू ने बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के अपने स्थान पर अपने भाई की स्वीपर के पद पर अंशकालीन दर पर नियुक्ति करवा दी। बाबू के पैर जमते ही वर्ष 1991 में पत्नी को अंशकालीन स्वीपर पद पर भर्ती करवा दिया, चुकी अंशकालीन से स्थाई कर्मी तक का सफर लम्बा ओर देरी वाला है, इसलिए बाबू ने पत्नी को दैनिक वेतन भोगी बनाने की जुग्गत की, जिसमे कामयाबी भी हासिल कर ली। बाबू ने अपनी पत्नी को दैनिक वेतन भोगी बनाने के लिए तत्कलीन प्राचार्य से मिलीभगत कर वर्ष 2005 में कन्या छात्रावास में रसोयन के पद पर पदस्थ महिला, जिसकी नियुक्ति सहायक आयुक्त झाबुआ के आदेश से हुई थी लेकिन तत्कालीन प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद ने वर्ष 2010 में पत्र जारी कर महिला रसोयन भंवर बाई का अटैचमेंट समाप्त कर दाडिया आश्रम भेजकर कार्य मुक्त कर दिया, जबकि नियमानुसार जिस अधिकारी ने अटेचमेंट किया है उसके आदेश से अटेचमेंट समाप्त होना था। योजनाबद्ध तरीके से महिला रसोंयन भंवर बाई को यहा से हटाकर तत्कालीन प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद ने बाबू की पत्नी को रसोयन के पद पर नियुक्ति के लिए 1 जुलाई 2010 को सहायक आयुक्त झाबुआ को अग्रेषित किया गया और पहले से जमी जमाई सेटिंग के चलते अगले ही दिन 2 जुलाई 2010 को बाबू की पत्नी का आदेश कलेक्टर दर पर कार्य करने के लिए पदस्थ कर दिया, लेकिन सहायक आयुक्त द्वारा जारी आदेश में किस पद पर बाबू की पत्नी को पदस्थ किया का उल्लेख नही किया और केवल कमला नेहरू कन्या छात्रवास पेटलावद में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्य हेतु अनुमति देकर कलेक्टर दर पर भुगतान करने का आदेश जारी किया। इतना ही नही कलेक्टर दर पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष बाद ही शासन के आदेशों का हवाला देकर स्थाई कर्मी करवा दिया गया। स्थाई कर्मचारियों की सूची में आदेश क्रमांक 1666/20 फरवरी 2018 को सहायक आयुक्त द्वारा जो सूची जारी की गई उस सूची में बाबू की पत्नी का नाम सरल क्रमांक 51 पर दर्ज है। जब बाबू की पत्नी को स्थाई किया गया जब फर्जी नियुक्ति को लेकर रमेश धानक द्वारा उच्च अधिकारियों को मामले की शिकायत की गई थी और मामले की जाँच चल रही थी, बाबजूद इसके सभी जांच व कायदे-कानून को खुटी पर टांग दिए गए, साथ ही सहायक आयुक्त ने 2 जुलाई 2010 को जो आदेश दिया उसमे बाबू की पत्नी को न तो दैनिक वेतन भोगी लिखा गया न ही रसोंयन का पद का उल्लेख किया। उक्त आदेश में कोई पद नही होते हुए भी बाबू की पत्नी को मिलीभगत कर तत्कालीन प्राचार्य योगेन्द्र प्रसाद के साथ मिलकर बाबू ने स्थाई कर्मी कर दिया।

कोरोना वैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण का ट्रायल शुरू

नई दिल्ली एजेन्सी। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफइंडिया ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफइंडिया से अनुमति मिलने के बाद कंपनी ने वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह ट्रायल 16 सौ वॉलंटियर्स पर किया जाएगा, जिनकी उम्र 18 साल या उससे उपर हो। देश के 17 स्थानों पर ट्रायल की व्यवस्था की गई है।

मानव तस्करों के चंगुल से दो बांग्लादेशी युवतियों को छुड़ाया, अवैध तरीके से पार कराई गई थी सीमा

नई दिल्ली एजेन्सी। बीएसएफ ने मानव तस्करों के चंगुल से दो बांग्लादेशी युवतियों को छुड़ाया है। दोनों युवतियों को भारत में काम दिलाने के नाम पर तस्करों ने अवैध तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कराई थी। यह घटना मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती क्षेत्र की सीमा चौकी, रनघाट के निकट हुई थी।

सीमा सुरक्षा बल को यह खुफिया सूचना मिली थी कि, कुछ तस्कर सीमा पार से युवतियों को लाने की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद बीएसएफने सीमा पर एक विशेष खोज टीम गठित कर दी। मंगलवार को रात 8 बजे जब बीएसएफके मुस्तैद जवान बैठे थे, तो उन्हें एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। इस पर तीन लोग बैठे थे।

निकट आए तो मालूम हुआ कि, बाइक पर दो महिलाएं बैठी हैं। संदिग्ध हरकतों के चलते उन्हें रूकने का इशारा किया गया। चूंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मोटरसाइकिल सवार और उसके साथ बैठी दोनों महिलाएं पीछे की तरफभागने लगीं। पीछा करने पर जवानों ने दोनों महिलाओं को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल सवार अंधेरे तथा झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़ी गई महिलाओं में एक ने अपनी उम्र 24 वर्ष बताई है। उसने बताया कि, वह विधवा है और जिला कोमिला, बांग्लादेश की रहने वाली है। दूसरी महिला ने अपनी उम्र 19 वर्ष तथा घर जिला-नरसिंग्डी, बांग्लादेश बताया है। महिलाओं से 6537 रुपये नकद (भारतीय रुपये), एक मोबाइल फोन तथा एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। आधार कार्ड के अनुसार मोटरसाइकिल चालक की पहचान तमीज मंडल (उम्र 19) पुत्र सिराजुल इस्लाम मंडल, कुलिया, रणघाट, जिला 24 परगना नॉर्थ, पश्चिम बंगाल के तौर पर हुई है।

सरपंच साहब फिल्म का काम जल्द होगा शुरू - महेश शुक्ला

माही की गूंज, पेटलावद

"आज फैसला मंजूर छे" की टीम यूनिट ने अपनी अगली फिल्म "सरपंच साहब" के लिए पत्रकार संघ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमे लेखक महेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि, अपनी पहली फिल्म "फैसला मंजूर छे" की अपार सफलता के बाद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित हो चुकी है और मेघसिंह पचाया ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमे आदिवासी समाज की कुरुतियों को दूर करने का और समाज में जागरूकता लाने के लिए बहुत ही अच्छे संदेश दिए थे। आज हम पुनः मेघसिंह पचाया और चिंतन गामड की मुख्य भूमिका में अतिशीघ्र "सरपंच साहब" नाम से एक सुंदर सी संदेशात्मक फिल्म बनाने जा रहे हैं। टीम यूनिट ने मीडिया बंधुओ और इस क्षेत्र की जनता से भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है, और आगे भी सभी के सहयोग की अपेक्षा रखते हुए जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू करने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।

कोविड-19 के बाद देश में गईं 1.9 करोड़ नौकरियां

नई दिल्ली एजेन्सी। कोरोना संकट अर्थव्यवस्था के लिए भी भारी पड़ रहा है। कोराना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण देश में करीब 1 करोड़ 89 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं. यही नहीं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जुलाई महीने में ही 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं थी।सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान करीब 1 करोड़ 7 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। जुलाई में तो हालत और खराब रही. जुलाई महीने के दौरान 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं।

जम्मू-कश्मीर से वापस बुलाई जाएंगी अर्धसैनिक बलों की सौ कंपनियां

श्रीनगर। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीर घाटी में बीते एक साल से तैनात पैरामिलिट्री की सौ कंपनियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अंत से पहले लगाई गई इन सभी कंपनियों को अब हालातों की समीक्षा के बाद वहां से हटाने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले को घाटी में विश्वास बहाली के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। करीब 12 हजार जवानों को वापस बुलाया जाएगा।

प्रबल सिपाहा की रवानगी, रोहित सिंह होगे झाबुआ के नए कलेक्टर

कलेक्टर रोहित सिंह

माही की गूंज, झाबुआ। जैसा कि लम्बे समय से जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा की रवानगी के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन स्थानीय राजनीतिक उठापटक के बीच कई बार हुई प्रशासनिक व्यवस्था में प्रबल सिपाहा का नाम नही आ रहा था, लेकिन बुधवार को जारी हुई प्रशासनिक फेरबदल में जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा की रवानगी हो गई जिन्हे लोक निर्माण विभाग का उपसचिव बनाया गया, वही जिला दतिया के कलेक्टर रोहित सिंह होगे झाबुआ जिले के नए कलेक्टर।

66 लाख स्वयं सहायता समूहों के विशाल नेटवर्क का होगा बेहतर उपयोग

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने मिलकर काम करेंगे केंद्रीय मंत्रालय

भोपाल

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग तक पहुंचाने के साथ ही आजीविका बढ़ाने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालय समन्वय के साथ अग्रसर होंगे। मंगलवार को इन मंत्रालयों की योजनाओं के तालमेल के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) प्लेटफार्म का लाभ उठाने के संबंध में वेबिनार हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में दोनों मंत्रालयों के बीच, जनजातीय क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी साइन किया गया। वेबिनार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता, संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी, राज्यों के ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी उपस्थित थे।

राष्ट्रहित में हो सकते हैं सकारात्मक परिवर्तन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तोमर ने इस अवसर पर कहा कि गरीबी उन्मूलन भारत सरकार की प्राथमिकता है। देश के कमजोर और गरीब वर्ग की शक्ति को एक सूत्र में पिरोकर इसका सदुपयोग किया जाए तो राष्ट्रहित में बड़े सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। सभी मंत्रालय मिलकर ग्रामीण, जनजातीय, महिला और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए एकजुट हैं। ग्रामीण गरीबों के जीवन में बदलाव लाने, उनका जीवन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है।

नेटवर्क तैयार करने में मिली मदद

तोमर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग तो मिलता है, लेकिन उनके उत्पादों के वैल्यू एडिशन और बाजार मिलने की समस्याएं आती हैं। उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा कि अब, जबकि सभी मंत्रालय मिलकर काम करेंगे तो ये कार्य आसान हो सकेगा। तोमर ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से देश में 66 लाख स्वयं सहायता समूह बनाकर 7.14 करोड़ परिवारों का नेटवर्क तैयार करने में मदद मिली है। स्वयं सहायता समूहों की बहनों ने कोविड-19 संकट के दौर में सभी की अपेक्षा से बहुत आगे बढ़कर योगदान दिया है। इनके द्वारा बनाए मास्क व सैनेटाइजर का उपयोग देशभर में कोरोना संक्रमण से बचाव में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालयों के आपसी तालमेल से स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण, प्रशिक्षण व विपणन के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीणों के जीवन स्तर में होगा नया सुधार

केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि यह एमओयू, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक नया अध्याय है। मंत्रालयों के आपसी समन्वय से ग्रामीण उत्पादक और बाजार के बीच की गैप आसानी से कम की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने कहा कि राज्य सरकारों को दूसरे राज्यों के उत्पादों को अपने यहां बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

आमिर पर भड़कीं उमा भारती, बोलीं-

तुर्की में फर्स्ट लेडी से मुलाकात दुखद और शर्मनाक

भोपाल। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद हिंदुस्तान में सियासी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी आमिर खान ट्रोल हो रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम उमा भारती भी आमिर खान पर भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि आप मेरे फेवरिट है, लेकिन देश हमारे लिए सबसे फेवरिट है। दरअसल, तुर्की कई मुद्दों पर भारत का विरोध करता रहा है। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अब अभिनेता आमिर खान ने तुर्की की पहली महिला एमीन एर्दोगन से मुलाकात की है। इसे लेकर हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सफल गाथाओं प्रतियोगिता आयोजन

भोपाल महिला-बाल विकास मंत्री इमरती देवी की पहल पर विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठा प्रयोग किया है। विभाग ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सफल गाथाओं का वीडियो संकलन प्रतियोगिता रखी है जिसमें प्रत्येक जिले के एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो के लिए आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जायेगा। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को "माँ के दूध का महत्व-माँ की जुबानी" विषय पर अधिकतम 60 सेकंड का वीडियो बनाकर 20 अगस्त तक www.amrutpaan.org पर एंट्री जमा करना होगा।

पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना म मध्यप्रदेश अव्वल

भोपाल। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में मध्यप्रदेश देश में नंबर एक पर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 58 हजार 476 स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त लोन स्वीकृत किया जा चुका है। यह देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों का 47 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंत तक एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का लोन स्वीकृत कर दिया जायेगा।

इंदौर में सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना

धुर विरोधी विजयवर्गीय के घर पहुंचे सिंधिया, दोनों की नहीं हो पाई मुलाकात

इंदौर

राम मंदिर निर्माण के भूमिपूजन को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है। मंदिर का ताला खुलवाने पर कमलनाथ और शशि थरूर ने अलग-अलग दावे किए हैं। इस पर सिंधिया ने निशासना साधा और कहा कि कांग्रेस को खुद पता नहीं उनके नेताओं ने क्या किया। सिंधिया एक समय में धुर विरोधी रहे कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे थे। उन्होंने इंदौर में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली।

बता दें कि एमपीसीए में अक्सर आमने सामने रहे कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का मिलन नहीं हो पाया, लेकिन सिंधिया ने उनके घर जाकर अपने गिले शिकवे दूर करने का प्रयास जरूर किया। कैलाश विजयवर्गीय की अनुपस्थिति में उनके बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया। सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय के घर खाना खाया और उनके परिजनों ने जब सिंधिया से मराठी में बात की तो सिंधिया गदगद हो गए।

पहले से तय था कार्यक्रम- अब सियासी गलियारे में इसी बात की चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के टूर प्रोग्राम में कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के लिए समय तय था। लेकिन कैलाश इंदौर में नहीं थे। हालांकि पार्टी के लोग इसके पीछे दलील दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में थे। जिस कारण दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के घर में सिंधिया का भव्य स्वागत किया गया। सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय के घर में ही डिनर किया।

सुमित्रा महाजन के घर भी गए सिंधिया

इससे पहले सिंधिया सुमित्रा महाजन और बीजेपी ऑफिस भी गए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के कार्यकाल के भ्रष्टाचार को जनता तक ले जाने की बात कही। भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार इंदौर आए थे। सिंधिया ने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि आप कांग्रेस से सवाल पूछिए। एक तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला पूर्व पीएम राजीव गांधी ने खुलवाया था।

दिग्विजय पर साधा निशाना

सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय के घर खाना खाया और मीडिया से खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दोनों नेता बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे में उनके बारे में क्या टिप्पणी की जाय। उन्होंने कहा कि जितना भ्रष्टाचार 15 महीनों की सरकार में हुआ वो उन्होंने कभी नहीं देखा। सिंधिया ने अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर कहा कि मौजूदा सरकार सभी के हित में काम करेगी।

इसपर नहीं दिया जवाब

दिग्विजय सिंह के ट्वीट 'चंबल का पानी गद्दारों से नफरत करता है' पर सिंधिया ने कहा कि मैं किसी के ट्वीट पर कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं, सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय के एमपीसीए के गिले शिकवों के दूर करने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन अगर जिंदगी में हम लोग अच्छे रिश्ते कायम कर पाएं तो इससे बड़ी पूंजी क्या होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता की चिंता है।

आकाश विजयवर्गीय रहे सिंधिया के साथ

कैलाश विजयवर्गीय के अनुपस्थिति में उनके घर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खूब आवभगत हुआ है। बीजेपी विधायक और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय उनके साथ रहे हैं। इसके साथ ही विजयवर्गीय के करीबी विधायक रमेश मेंदोला भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहे हैं। दोनों नेता ज्योतिरादित्य सिंदिया को रिसीव करने एयरपोर्ट भी गए थे।

कांग्रेस ने किया वार

वहीं, कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात नहीं होने पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार किया है। नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा है कि आंच अगर उसूलों में आए तो टकरा जाना चाहिए, सम्मान की दुहाई देने वाले श्रीअंत का ऐसा हुआ सम्मान? मेहमान घर पर और मेजबान नदारद, कहां अलग से राजसी ठाठ से बैठते थे और अब कहां लाकर समर्थकों के साथ बैठा दिया। ऐसा झटका दिया कि चेहरे का नूर चूरा उड़ा दिया।

मंत्री पटेल ने कहा- बिना सोचे-समझे लिया गया था निर्णय

कन्या विवाह योजना में भाजपा सरकार नहीं देगी 51 हजार रुपए

भोपाल

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कन्या विवाह योजना में 51 हजार रुपए की राशि को कम करने जा रही है। शिवराज सरकार ने कांग्रेस सरकार के इस बड़े फैसले को पलटने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद शिवराज सरकार में कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली 28 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया था। सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना सोचे-समझे कई बड़े फैसले कर लिए थे, जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया और ऐसे हजारों मामले अभी पेंडिंग हैं। अब शिवराज सरकार के मंत्री पटेल ने साफ कर दिया कि जिन हितग्राहियों को 51 हजार रुपए राशि का वितरण नहीं हो सका, उनको मौजूदा सरकार नहीं देगी।

28 हजार रुपए ही दिए जाएंगे: मंत्री

मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार से पहले भाजपा सरकार में दी जाने वाली 28 हजार रुपए की राशि को यथावत रखने का फैसला कर सकते हैं। इस पर आखिरी फैसला उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया जाएगा। इधर, भाजपा सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर योजना में बदलाव किया गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कन्यादान योजना अच्छी है। कमलनाथ सरकार ने राशि बढ़ाई थी, राशि कम करना गरीब परिवारों के साथ कुठाराघात होगा।

20 हजार से ज्यादा जोड़ों को नहीं मिली धनराशि

15 साल के बाद 2018 में कांग्रेस सरकार आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले किसान कर्ज माफी और दूसरी कन्या विवाह योजना की राशि को बढ़ाने की फाइल पर दस्तखत किए थे। इसके तहत कन्या विवाह योजना में लड़कियों की शादी पर अनुदान राशि 28 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार की गई थी, लेकिन सरकार की तंगहाली के कारण करीब 20 हजार जोड़ों को इस योजना के तहत राशि का वितरण नहीं हो पाया और तब भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला था और अब सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने पिछली सरकार के पात्र हितग्राहियों को राशि देने से इनकार कर दिया है।

जीआई टैग विवाद पर कृषि मंत्री ने कहा

दिग्गी शिवराज की बजाय पंजाब को लिखे चिट्ठी

भोपाल

मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जी आई टैग दिए जाने के मामले पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जीआई टैग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी गई चिट्ठी के जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। कमल पटेल की मानें तो दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए, जो मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिलने का विरोध कर रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह भी कहा है कि 15 महीनों तक मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी। तब दिग्विजय सिंह ने जीआई टैग का मुद्दा आखिरकार क्यों नहीं उठाया। कमल पटेल की मानें तो मध्य प्रदेश सरकार बासमती चावल को जी आई टैग दिलाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

दिग्विजय ने शिवराज को लिखा था खत

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जीआई टैग के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि प्रदेश में बासमती धान का उत्पादन करने वाले किसानों के प्रति आप (शिवराज) एकाएक बहुत चिंतित और विचलित हो रहे हैं। आपकी वेदना है कि प्रदेश के किसानों द्वारा पैदा की जा रही बासमती को अभी तक एपीडा संस्था से जीआई टैग नहीं मिल पा रहा है। आप प्रदेश के किसानों के इतने बड़े शुभचिंतक हैं। दिसम्बर 2003 से लेकर विगत सवा साल छोड़कर करीब सोलह साल से आप की प्रदेश में सरकार है। बासमती की टैगिंग को लेकर आपने बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं किया। यही नहीं भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को सातवां साल चल रहा है। अब तक टैग क्यों नहीं दिला सके।

क्या है मामला?

मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल की जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग देने पर नाराजगी जताई थी। इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इसी पर एमपी सरकार ने नाराजगी जताई और सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कमलनाथ से पूछा था कि कांग्रेस बताए वो पंजाब के किसानों के साथ है या एमपी के किसानों के साथ।

पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने सरकार पर साधा निशाना, कहा-

चुन-चुनकर थमाए जा रहे हैं बंगला खाली करने के नोटिस

एसी-एसटी के नेताओं से खाली करवाए जा रहे बंगले

भोपाल

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने प्रदेश की शिवराज सरकार को अंधी, बहरी, गूंगी, लूली और लंगड़ी सरकार बताया है। सुश्री साधौ ने पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली करवाने के मुद्दे पर भाजपा की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार चुन-चुनकर विधायकों और पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करवाने का नोटिस दे रही है। साधौ ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में 15 महिने हमारी सरकार ने भाजपा के कई नेता जो मंत्री पद पर नहीं रहे उनको कभी बंगला खाली करवाने का नोटिस नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि मंत्री भूपेन्द्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, सुरेन्द्र पटवा, कृष्णा गौर, दीपक जोशी जैसे भाजपा नेता कमलनाथ सरकार के दौरान सरकारी बंगलों में रहे, लेकिन कांग्रेस ने द्वेषपूर्ण कार्यवाही नहीं की।

किसी की बपौती नहीं हैं सरकारी बंगले

पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकारी बंगलों पर मेरी और न किसी और की बपौती नहीं है, पर विधानसभा ने अपने सदस्यों के लिए नियम कानून बनाए है। इसके आधार पर वह इन बंगलों में रहने के पात्र है। जिसकी यह अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी सरकार अनदेखी कर रही है। साधौ ने कहा कि शिवराज सरकार इस कोरोना काल में भेदभाव पूर्व रवैया अपनाकर एससी और एसटी विधायकों और पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली करवाने नोटिस भेज रही है। जिसमें दो एससी विजयलक्ष्मी साधौ और सज्जन वर्मा तथा दो एसटी बाला बच्चन और उमंग सिंघार को नोटिस दिए गए हैं।

अनुसूचित-जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने बैठक में की समीक्षा

अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर मिले छात्रवृत्ति की राशि

भोपाल

अनुसूचित-जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों में समय पर पहुँचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग के लोगों के कल्याण की योजनाओं में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा। मीना सिंह आज मंत्रालय में हुई बैठक में अनुसूचित-जाति वर्ग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। बैठक में प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल भी मौजूद थीं। अनुसूचित-जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में जिन चयनित युवाओं को मदद दी जा रही है, उन्हें यूपीएससी, पीएससी सेवा परीक्षा के अलावा अन्य शासकीय सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के संबंध में मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि जिन युवाओं को यह छात्रवृत्ति दी गई है, उन्हें उसके अनुरूप रोजगार मिले, वह भी सुनिश्चित किया जाये।

केरल के कांग्रेस सांसद ने सोनिया गांधी से की थी शिकायत

कमलनाथ ने बदली ट्विटर प्रोफाइल, फिर पुराने रूप में आए नजर

पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर बदली है। 5 अगस्त को उन्होंने भगवा पहनकर एक धार्मिक स्थल की अपनी तस्वीर लगाई थी। 15 अगस्त को उन्होंने अपनी दूसरी तस्वीर ट्विटर पर प्रोफाइल लगाई है। तस्वीर बदले जाने के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ के अयोध्या के श्रीराम मंदिर भूमिपूजन का स्वागत करने पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर केरल के त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को शिकायती पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी।

अयोध्या में भूमिपूजन से पहले कमलनाथ ने अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया

भोपाल

अयोध्या में भूमिपूजन से पहले कमलनाथ ने अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पार्टी द्वारा प्रदेश भर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। 5 अगस्त को भूमिपूजन के बाद शाम को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने राम दरबार सजवाया और वहां बैंडबाजों के साथ भगवान राम की आरती की थी। आरती के बाद कमलनाथ ने कहा था कि वे राजीव गांधी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ताले राम मंदिर के खोले थे। राम मंदिर की कहानी वहीं से शुरू होती है। हम मध्य प्रदेश की जनता की ओर से 11 चांदी की ईंट अयोध्या भेज रहे हैं। ये ईंटें कांग्रेस सदस्यों ने दान देकर खरीदी हैं।

टीएन प्रतापन ने सोनिया गांधी को शिकायती पत्र लिखा था

- राम मंदिर निर्माण के भूमिपूजन का कमल नाथ और दिग्विजय सिंह द्वारा स्वागत करने पर केरल के कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को शिकायती पत्र लिखा था।
- उन्होंने दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाओं को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे भागना बताया था। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और बहुल वादी है, लेकिन हमें उस हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भाजपा और आरएसएस का है।
- प्रतापन ने सोनिया को लिखे पत्र के बारे में पूछे जाने पर कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय की प्रतिक्रिया बहुत खराब थी। कांग्रेस का रुख भाजपा के हिंदुत्व के रुख का समर्थन करना नहीं है। मेरा नाम प्रतापन है, मैं भी हिंदू हूं। मैं भगवान की आराधना करता हूं।

शिकायती पत्र के बाद क्या कहा था कमलनाथ ने

इस शिकायती पत्र पर कमलनाथ ने कहा था कि राम मंदिर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो रुख था, मैं उसी पर हूं। इसे किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। राजीव जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। हम बाबरी मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ थे। कांग्रेस का रुख साफ था कि हम इस पर अदालत के फैसले का पालन करेंगे। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया था। मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूं लेकिन, मैं अन्य सभी धर्मों का अत्यधिक सम्मान करता हूं। क्या भाजपा ने हिंदू धर्म का पेटेंट कराया है। क्या उन्होंने (भाजपा) धर्म और भगवान राम के लिए एजेंसी ली है।

बदली हुई सरकार में बिजली बिल के झटके, भारी भरकम बिलों से जनता परेशान

शिवराज सरकार में बिजली बिल के नाम पर हो रही ठगी–कांग्रेस

माही की गूंज, पेटलावद राकेश गेहलोत

15 माह की कांग्रेस सरकार में आम जनता को बिजली बिल को लेकर भारी राहत मिली थी, लेकिन सरकार बदलते ही आम जनता भारी भरकम बिलो के बोझ तले परेशान हो रही हैं, अचानक बिल की राशि मे हुई 10 गुना तक की वृद्धि आम जनता की समझ से परे है, क्योकि जो बिल चार माह पूर्व 500 से 1000 रुपए

महीने के आ रहे थे वही आज बढ़ कर 5000 से 10000 हजार तक पहुच गए है, उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नही है। आलम ये है कि, दो-तीन हजार रुपए महीना किराए से रहने वाले भी 02 से 03 हजार रुपये का बिल भरने पर मजबूर हो गए जो पहले बमुश्किल 500 रुपए तक का बिल भरते थे। ऐसे एक-दो नही सैकड़ो मामले सामने आ रहे है, जहाँ बिल को लेकर आम जनता की भड़ास आम जनता पर निकल रही है। पेटलावद के दिनेश राठौर का बिल पिछले चार माह से पांच हजार से अधिक आ रहा है शुरुआत में एक-दो बिल जमा कर दिए लेकिन बिजली विभाग द्वारा लगातार राशि बड़ाकर ही बिल भेजे जा रहे है, दिनेश राठौर ने बताया कि, मेरे द्वारा पिछले दो माह में 6 हजार ओर फिर 9 हजार से अधिक का बिल जमा करा दिया गया लेकिन इस माह फिर 9 हजार से ज्यादा का बिल विभाग ने थमा दिया। जब बिजली विभाग से इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि, हम कुछ नही कर सकते जो बिल आया है वो भरना ही पड़ेगा, इससे पहले भी नीलेश सोनी के बन्द पड़े घर का हजारों रुपये का बिल विभाग ने थमा दिया जिसका निराकरण सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद हुआ, वही भरत चौधरी का कहना है कि, भरी गर्मी और कोचिंग सेंटर चलने के दौरान भी कभी इतना बिल नही आया अभी लगातार 9 हजार का बिल दिया जा रहा है, चेक मीटर लगाने के बाद भी कोई फर्क नही पड़ा अब मीटर बदलने के लिए आवेंदन किया है, लेकिन लगता नही कोई फर्क पड़ने वाला है। बिजली बिल भर पाना मुश्किल होता जा रहा है, कई गरीब लोगों के बिल तो इतने अधिक आ रहे हैं कि, उनके लिए बिल भर पाना किसी भी स्थिति में संभव नही है। वर्तमान सरकार में बिजली के बिल पिछली सरकार के बिलो से तीन से चार गुना से लेकर दस गुना तक वृद्धि कर दिए जा रहे है, कोविड-19 ने पहले से आम-जन की कमर तोड़ रखी है, ऐसे में भारी-भरकम बिजली के बिल से लोगो को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, वही बिजली उपभोक्ताओ को समझ नही आ रहा हैं आखिर बिल की राशि और यूनिट में इतना फर्क कैसे आ रहा हैं।

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप, विधायको को खरीदने के लिए खर्च किए पैसे, आमजनता से वसूले जा रहे हैं

बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान आमजनता के लिए कांग्रेस नेताओ ने वर्तमान की शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जीवन ठाकुर ने बताया कि, कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में बिना भेदभाव के हर वर्ग को बिजली बिल में राहत मिले इसका सफल प्रयाश किया था और लोग आज कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं, लेकिन सरकार बदलते ही भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बिजली बिल के नाम पर सीधे आमजनता का गला काटा जा रहा है। वही विघायक प्रतिनिधि मन्नालाल हामड़ का कहना है कि, शिवराज सरकार ने गलत तरीके से विधायको की खरीद फरोख्त कर मध्यप्रदेश की जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा कर अपनी सरकार बना ली और अब भाजपा आमजनता से बिजली बिल के नाम पर सरकार गिराने के लिए खर्च की हुई राशि वसूल रही है, आने वाले चुनाव में भी पैसे के दुरुपयोग के लिए वशूली बिजली विभाग के माध्यम से की जा रही हैं। बिजली बिल के नाम पर आम जनता का खून चूसा जा रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है और उपचुनाव में भाजपा को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

खुद भाजपाई बिजली बिल से परेशान

सरकार का हिस्सा बने हुए कई भाजपाई खुद बढे हुए बिल से परेशान हैं, लेकिन सरकार के विरोध में नही जा रहे वही कई भाजपा के जनप्रतिनिधियों को बाजारों में अपनी ही सरकार के खिलाफलोगो से खरी-खोटी सूनने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगो का कहना है कि, छोटे-छोटे मुद्दे भुनाने वाली भाजपा के लोग सरकार में होने के कारण बड़े हुए भारी भरकम बिजली बिल की सरकार से गुहार लगाते नही दिख रहे।

भाजपा महिला मोर्चा की पहल

जिलेभर में लंबोदर के आगमन की तैयारी, घर-घर विराजेगे मिट्टी के गणपति

माही की गूंज, झाबुआ

कोरोना काल को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़े गणेश पांडाल पर रोक के साथ-साथ बड़ी गणेश प्रतिमा न बनाने के दिशा निर्देश मूर्तिकारों को जारी किए थे। भगवन की भक्ति और शक्ति के बिच इन दिनों प्रथम पूज्यनीय भगवान गणेश उत्सव की तैयारीयो में झाबुआ जिला भी जुटा है। इसी बिच झाबुआ भाजपा महिला मोर्चा ने जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक के मार्गदर्शन, श्रीमती सूरज गुमानसिंह डामोर की संदर्शिका व भाजपा महिला मोर्चा जिलाअध्यक्ष श्रीमती आरती भानपुरिया के नेतृत्व में पर्यावरण का संदेश देने के लिए मिट्टी के गणपति जिले भर में तैयार करने का प्रशिक्षण अभियान चलाया हैं।

महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमति आरती भानपुरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, मिट्टी के गणेश अभियान प्रशिक्षण की शुरुआत मंगलवार को मेघनगर विश्वकर्मा मंदिर, ग्राम खवासा में श्री भगत निवास स्थान एवं झाबुआ के राजवाड़ा गणेश मंदिर के साथ बुधवार को पेटलावद, रायपुरिया, राणापुर, पारा में भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गणेश प्रतिमा निर्माण के लिए बरगद, पीपल, नीम सहित कई तरह के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उन्हें प्रतिमा के बिच में रखा जाए और जब गणेश विसर्जन किया जाए तो पौधा तैयार हो सके। साथ ही फिटकरी के गणपति भी तैयार किए गए हैं, उन्हे विसर्जिन करने पर तालाब का पानी साफ रहे। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रशिक्षण देने के लिए माटी कला बोर्ड के एक सदस्य जो कि मिट्टी की मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट है, उनके द्वारा जिले भर की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खवासा में प्रशिक्षण के दौरान कई बहनों ने सुपारी एवं लच्छे के गणपति को भी शानदार आकार देकर साथी बहनो को प्रशिक्षित किया। पूरे अभियान और आयोजन के पीछे झाबुआ भाजपा महिला मोर्चा का लक्ष्य है कि, वह हर शहर व गांव में जाकर जिले भर की सौ बहनों को प्रशिक्षण दें और 100 बहने 1000 बहनो को मिट्टी के गणेश जी बनाना सिखाएं ताकि घर-घर में हाथ से बने विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश को विराजित किया जाए।

पर्यावरण सहेजने की दिशा में यह कार्य

श्रीमती सूरज गुमानसिंह डामोर ने बताया कि, पर्यावरण पर ध्यान देना आवश्यक है और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना हम सभी का कर्तव्य है। इस बार घर में हाथ से बनी बप्पा की मूर्ति की स्थापना करना है, मूर्ति का विसर्जन भी घर में करना है। हमारे जिले में मिट्टी के गणपति बनाने में प्रशिक्षण में सभी महिलाएं जुटी हैं, यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी हमारी परंपरा और रीति-रिवाज को ध्यान में रखा जा रहा है।

इन महिलाओं ने प्रशिक्षण में लिया भाग

मेघनगर विश्वकर्मा मंदिर पर मेघनगर जनपद अध्यक्ष सुशीला भाभर, श्रीमती सरिता चौहान, श्रीमती मोटवानी, श्रीमती शर्मा, समाजसेविका रेशमा, श्रीमती योग्यता प्रजापत, श्रीमती सिंघल, श्रीमति टीना शर्मा, सुनिता चौहान, श्रीमती टीना, श्रीमती तरुणा गुप्ता, सिद्धिविनायक गणेश मंडल की महिलाएं व नन्ही बालिकाओं ने भी शिरकत की। खवासा में भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंजू पाटीदार, राधा बाई पाटीदार, ज्योति व्यास, दुलारी पटेल आदि महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया।

थांदला में कोरोना का हो रहा तांडव फिर भी नहीं रख रहे कोई सर्तकता

माही की गूंज, थांदला मुकेश भटट्

थांदला में कोरोना का तांडव लगातार जारी है जबकि व्यापारियों को अपने व्यापार की पड़ी है, यही व्यापारी बाहर अपने वाहनों से जाते हैं और कोरोना बाहर से लेकर आते हैं अभी भी समय है कि, थांदला को पूरा 15 दिनों तक लॉकडाउन करे नहीं तो पूरा थांदला कोरोना मय हो जायेगा। बुधवार की रिपोर्ट में 3 नए कोरोना पॉजिटिव सुबह की रिपोर्ट में आते हैं, उनमें से वार्ड 3 का पार्षद भी पॉजिटिव आया है और वार्ड नं 3 का एक हेयर सेलून दुकान का व्यक्ति भी पॉजिटिव आया है। थांदला के कुछ गैरजिम्मेदार लोगों के कारण ही यह कोरोना नगर में बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में ओर ले-लेगा। वही नगर परिषद भी कोरोना की चपेट में आएगा माना जा रहा है, सीएमओ ने भी अपने ईके दुक्के कर्मचारी की जॉच करवाई है, नगर परिषद में रोजाना कितने ही लोग आते-जाते हैं वो भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं।

बेटे को परीक्षा दिलाने 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर धार पहुंचा मजदूर पिता,

माही की गूंज, धार

प्रदेश में रुक जाना नहीं अभियान के तहत 10वीं-12वीं परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थीयो को एक और मौका दिया जा रहा है, मंगलवार को 10वी का गणित का पेपर था। जिले के मनावर तहसील के मजदूर शोभाराम के बेटे आशीष को 10वी में तीन विषय में असफलता मिली है जिसकी परीक्षा देना है। परीक्षा केंद्र उसके गांव से 105 किमी धार में है। कोरोना संक्रमण के चलते बसें बंद होने की वजह से शोभाराम अपने बेटे को लेकर सोमवार रात 12 बजे साइकिल से ही निकल पड़े। धार में ठहरने की व्यवस्था न होने से तीन दिन का खाने का सामान भी अपने साथ लाए। रात में 4 बजे मांडू और मंगलवार सुबह पेपर शुरू होने से मात्र 15 मिनट पहले पौने 8 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचे। बुधवार को सामाजिक विज्ञान और आज अंग्रेजी का पेपर है, दोनों पिता और पुत्र परीक्षा पूरी होने तक यहीं ठहरे है। पिता शोभाराम का कहना है कि, मैं मजदूर हूं लेकिन बेटे को मजदूरी नहीं करने दूंगा, इसलिए पैसे उधार लेकर परिक्षा दिलाने के लिए साइकिल से आया वही शोभाराम की मंशा अपने बेटे को अफसर बनाने का है। गांव में कोचिंग की व्यवस्था नही होने के कारण बेटा तीन विषय में असफल हुआ था पर वह अभी परिक्षा देकर अवश्य सफल होगा।

पंचायत की लापरवाही के कारण कीचड़ में निकलने को मजबूर ग्रामीणजन

माही की गूंज, खच्चरटोडी विकास साबलिया

मेघनगर से महज 4 किमी दुर स्थित खच्चरटोडी ग्राम पंचायत की लापरवाही ग्रामीणों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। दरसल शासन ने रूरल कनेक्टिविटी के लिये फत्ताटोडी गांव से खमतलाई तालाब तक सुदुर सड़क स्वीकृत की लेकिन पंचायत की लापरवाही के कारण बारिश में ये सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों का पेदल निकलना भी मुश्किल हो गया है, ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जनपद के अधिकारियों से भी सम्पर्क किया लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नही किया गया, फत्ताटोडी गांव के लिए आने-जाने का एक मात्र यह रास्ता है। ग्रामीणों का कहना है कि, हमने सोचा था की ये सुदुर सड़क बनने से हमको काफी सुविधा हो जायेगी लेकिन हालात पहले से ज्यादा बतर है, इससे बेहतर तो पहले इस रास्ते से निकलना था। बता दे कि, इस गांव के ग्रामीणों ने पक्की सड़क बनवाने के लिये क्लेक्टर के पास जाकर भी शिकायत की थी लेकिन आज तक इन ग्रामीणें की समस्या का हल प्रशासन नही कर पाया है।

पंचायत पर लापरवाही का आरोप

ग्रामवासियों का आरोप है कि, पंचायत ने इस सड़क को बनाने मे काफी लापरवाही ओर अनियनिताएं की। पंचायत यदि गंभीरता से लेती तो सड़क का काम कभी से पुरा हो जाता है। जहा विवाद था वही काम बंद करना था, लेकिन पुरी सड़क अधुरी छोड दी। पंचायत की इस लापरवाही के कारण हम इस समस्या से जुझ रहे है। वर्तमान में बारिश के कारण सडक कीचड़ मे तब्दील हो गई है जहा से पैदल निकला भी अब मुश्किल हो गया है

इस सम्बंध में जिला सीईओ सिद्धार्थ जैन से बात की तो गूंज को बताया, ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही होनी चाहिए इसलिये जनपद सीईओ से बात कर उन्हे निर्देश देता हु की जल्द ही ग्रामीणों की इस समस्या को हल किया जाए।

लापरवाही-कोरोना मरीज को निजी वाहन से जाना पड़ा जिला चिकित्सालय, 5 दिन बाद तक नही आई सेम्पल की रिपोर्ट

माही की गूंज, झकनावदा आंनद सोलंकी

ग्राम झकनावदा में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह बना बैठा है। पहला मामला सामने आने के बाद रात में मरीज को लेने स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नही आई और अगले दिन का बोल दिया गया। दूसरे दिन सुबह से स्वास्थ्य विभाग की टीम का इंतजार करने के बाद भी टीम नही आई तो आखिर घर के ही निजी वाहन से शाम को जिला अस्पताल जाना पडा। मामला सामने आने के बाद जिस तरह से कंटेनमेंट झोन बनाया गया उसमे से किसी का भी आना-जाना चालु है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोरोना मरीज के घर के आसपास का एरिया सील किया गया, किंतु स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है, ना तो उसे सैनिटाइज किया गया है और जो कोरोना मरीज के संपर्क में आए वो घर पर क्वॉरेंटाइन है, लेकिन उनका न तो हेल्थ चेकअप किया गया न ही सैनिटाइज किया गया, साथ ही जिस बंगाली डॉक्टर लक्ष्मी मंडल ने कोरोना मरीज का इलाज किया था, उसका प्राइवेट क्लिनिक धडल्ले से संचालित हो रहा है। जिससे एक बात साफजाहिर होती है, प्रशासन अभी भी घोर लापरवाही करते हुए इस कोरोना को और अधिक फैलाने का प्रयास कर रहा है।

अभी तक नही आई रिपोर्ट, लोग घूम रहे हैं आराम से

कोरोना संक्रमण की चपेट में आई महिला के परिजनों सहीत कंटेनमेंट झोन से लभगभ 40 लोगो के सेम्पल लिए गए है, जिसकी जाँच रिपोर्ट 5 दिन बाद तक नही आई है, जबकि झकनावदा से लिए गए सेम्पल की कोई रिपोर्ट अभी तक नही आई है। वही कंटेनमेंट झोन में लोगो का आना-जाना बे रोक-टोक जारी है, जिनको रोकने की कोई व्यवस्था नही नही है, जो नगरवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

मिर्ची में वायरस का प्रकोप, किटनाशक दवाई का भी नहीं हो रहा असर, अब छाछ व शराब का देशी छिड़काव कर रहे किसान

माही की गूंज, खवासा जितेन्द्र पाटीदार

कोविड-19 रूपी अदृश्य वायरस के खिलाफपूरी मानव जाति जंग लड़ रही है और वर्ष 2020 की शुरुआत से ही परेशानियों का सामना हर कोई कर रहा है, इसी बीच अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जुलाई माह सूखा बीतने के पश्चात कृषकों की उम्मीद थी कि, अगस्त में अच्छी बारिश होगी लेकिन अगस्त माह के तीसरे हफ्ते के बाद भी कृषकों को झमाझम वर्षा का इंतजार है, मालवा में एक कहावत प्रचलित है कि, ''दुबले और दो अषाढ़'' यानी विपत्ति पर विपत्ति या दोहरी विपत्ति आना, कुछ ऐसी ही स्थिति इन दिनों क्षेत्र के किसानों की हो रही है। एक तो अच्छी बारिश नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्य नगदी फसले बीमारी की मार झेल रही है। क्षेत्र की मुख्य नगदी फसलें टमाटर और मिर्ची है तथा क्षेत्र के टमाटर और मिर्ची देश के कई हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं, यहां तक की पाकिस्तान तक भी बॉर्डर के हालात सामान्य होने तक गया। टमाटर और मिर्ची ने किसानों को उन्नति की नई राह दिखाई है, लेकिन इन दिनों इन फसलों पर अज्ञात वायरस का खतरा मंडरा रहा है, अच्छी लहराती फसलों के पत्ते सिकुड कर हरे पौधो में पिलास पन व सफेद पड़ रहे हैं, तथा उनमें छेद भी हो रहे हैं। कृषक तमाम प्रयास कर रहे हैं और कीटनाशक का भी उन पर असर नहीं हो रहा है, ऐसे में कृषक का चिंतित होना स्वाभाविक है, कई खेतों में ये ही स्थिति हो रही है। कृषकों ने बताया कि, इन पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है थक-हार कर किसान अन्य प्रयास भी कर रहे हैं कुछ किसानों ने बताया कि, फसल का देशी उपचार करते हुए अब फसलो पर छाछ व देशी शराब मदिरा आदि का भी छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। कृषकों की इन चिंताओं के प्रति सरकार का ध्यान देना आवश्यक है, लॉकडाउन के बाद में किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, ऐसे में इस फसल में वायरस ने भी दोहरा प्रहार किया है।

संपादकीय

कोरोना महामारी आत्मनिर्भरता का बड़ा सबक

देश के 74 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से संबोधित किया। यह एक औपचारिक परंपरा है, लेकिन देश के भीतर आजादी और एकजुटता के एहसास को पुख्ता करती है। जज्बे और जुनून को जिंदा रखती है, लिहाजा यह दिन और संबोधन दोनों ही हमारे लिए पावन स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। अक्सर प्रधानमंत्री लालकिले से किसी नई योजना, नई नीति या नए कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। उसकी अवधि भी देश को बताई जाती है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने कोई नई घोषणा नहीं की। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात पुरानी है। ऑप्टिल फाइबर नेटवर्क का काम पहले से ही जारी है और करीब 1.5 लाख पंचायतों तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने इतना आश्वासन जरूर दिया कि आगामी 1000 दिनों में शेष छह लाख गांवों और लक्षद्वीप को भी इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। कोरोना टीके का लक्ष्य 15 अगस्त के लिए तय किया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शोधार्थियों ने जल्दबाजी पर सवाल उठाए, तो घोषणा को वैज्ञानिकों की हरी झंडी के हवाले कर दिया गया। अलबत्ता प्रधानमंत्री ने माना कि कोरोना हमारी आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा सबक साबित हुआ है। बहरहाल सीमावर्ती और तटीय इलाकों में एनसीसी के एक लाख कैडेट्स तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने का ऐलान किया गया है, ताकि वे सेनाओं में सेवा देने के योग्य बन सकें। इनमें एक-तिहाई लड़कियां भी होंगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा में कुछ नवीनता है, लेकिन यह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, लिहाजा उसे लालकिले से की गई नई, ऐतिहासिक घोषणाओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी के 86 मिनट के संबोधन का इस बार थीम रहा-आत्मनिर्भरता। उन्होंने बार-बार आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास, सक्षम और सशक्त भारत की बात कही। प्रधानमंत्री की व्याख्या थी कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची आजादी है। स्वतंत्र भारत की उम्र 73 साल हो चुकी है। वैसे तो यह बुढ़ापे की उम्र है, लेकिन आजादी के बाद का इतना कालखंड भी, सब कुछ हासिल करने के मद्देनजर, पर्याप्त नहीं है। फिर भी भारत अपने क्षेत्र का 'सिकंदर' है। उसने बार-बार अंतरिक्ष में दस्तक दी है, सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व में अव्वल है, खाद्यान्न में स्वावलंबी है, व्यापक स्तर पर निर्यात करता है, कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, मिसाइल अनुसंधान और विकास को लेकर कई 'मील-पत्थर' स्थापित कर चुका है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्वाचित सदस्य भी है। आजाद और आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियां एक आलेख का विषय नहीं हो सकतीं। इस्पात, एल्यूमीनियम, जूते, फर्नीचर, चमड़ा और एयर कंडीशनर सरीखी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना है, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें। इनके अलावा लिथियम बैटरी, एंटीबॉयोटिक्स, पेट्रोकेमिकल, ऑटो, मोबाइल पार्ट्स, खिलौने, टीवी सेट, खेल के सामान आदि उत्पादों की लंबी सूची है, जिनमें आत्मनिर्भर होने की शुरुआत की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत और नई रणनीति के तहत भारत की नजर चीन से निकलने वाली कंपनियों को आकर्षित कर 'ग्लोबल सप्लाई चेन' बनने की है। करीब 300 कंपनियों से भारत सरकार की बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री का कहना है-हम कब तक कच्चा माल बाहर भेजकर तैयार वस्तुओं का आयात करते रहेंगे? लिहाजा 'मेक इन इंडिया' को पुख्ता किया जाए और इसे विस्तार देकर 'मेक फॉर वर्ल्ड' का नारा दिया जाए। प्रधानमंत्री ने देश को बताया कि कोरोना काल होने के बावजूद देश में विदेशी निवेश की रिकॉर्ड 18 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं और यहां आकर व्यापार करना चाह रही हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन में यह संदेश भी निहित था कि देश का आयात बिल कम किया जाए। ऐसा करने से ही हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता सिर्फ कारोबार और बाजार तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री इसे एक शब्द के बजाय जीवन-मंत्र मान चुके हैं। जब उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही चेतावनी दी कि भारत की संप्रभुता पर किसी की आंख उठी, तो उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा, तो ऐसा सामर्थ्य आत्मनिर्भर देश ही दिखा सकता है। प्रधानमंत्री ने प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत और नए कश्मीर के भी जिक्र किए, लेकिन सकारात्मक यह रहा कि उन्होंने जीत या हार के भाव नहीं दिखाए, बल्कि शांति, समरसता और सद्भाव की बात कही और उनकी महत्ता पर फोकस करते हुए कहा कि एक आत्मनिर्भर देश के लिए ऐसी संतुलित सामाजिक स्थितियां बेहद जरूरी हैं। प्रधानमंत्री का यह संबोधन भी देशव्यापी माना जाना चाहिए, क्योंकि वह सभी को जोड़ने की बात भी कर रहे हैं।

मोदी की राष्ट्रभक्ति ही गीता.. अब समान नागरिक संहिता... ?

ओमप्रकाश मेहता, लेखक

विश्व के सभी लोकतंत्री देशों में संभवतरू भारत अकेला ऐसा देश होगा, जिसकी सरकार ने मात्र सोलह महीनों के अब तक के कार्यकाल में सत्तारूढ़ दल के चुनावी घोषणा-पत्र के सभी बिन्दूओं को मूर्तरूप दे दिया। जी हाँ, देश की मौजूदा नरेन्द्र मोदी सरकार का करिश्मा है, सबसे अहद् अयोध्या राममंदिर को मूर्तरूप देना है, जो पिछले पाँच शताब्दियों से विवादित था।

अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र का एक ही मुद्दा शेष रह गया है, समान नागरिक आचार संहिता लागू करना, यदि कोरोना महामारी, लॉक-डॉउन आदि का संकट नहीं होता तो इस मुद्दे को भी मूर्तरूप मिल जाता, किंतु चूंकि अभी मोदी जी की सरकार का डेढ साल पूरा होने में दो महीने शेष है, इसलिए उम्मीद की जा रही है, इस अवधि में इस एकमात्र शेष रहे बिन्दू को भी मूर्तरूप देकर देश में लागू कर दिया जाएगा।

वैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान गैर-भाजपाई दलों का सत्तारूढ़ भाजपा के प्रधानमंत्री पर यही गंभीर आरोप था कि पांच साल के शासनकाल में मोदी सरकार ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, किंतु अब अपने दूसरे शासनकाल में मोदी जी की प्रमुख मुद्दों के प्रति सक्रियता को देख स्वयं प्रतिपक्ष हतप्रभ है, अभी तो इस कार्यकाल की डेढ़ साल की ही अवधि पूरी होने जा रही है, अभी साढ़े तीन साल (मई 2024 तक) की अवधि शेष है, इन शेष 42 महीनों की अवधि में क्या-क्या नए आयाम स्थापित होंगे? फिलहाल उनकी कल्पना भी मुश्किल है।

यदि हम मोदी जी के इस द्वितीय शासनकाल की अब तक की उपलब्धियों की चर्चा करें तो सबसे अहद् उपलब्धि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की विदाई है, इस एक संवैधानिक अनुच्छेद के कारण जम्मू-कश्मीर भारत से अलग-थलग विशेष अधिकार प्राप्त राज्य माना जाता था। मोदी जी ने पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का यह विशेष दर्जा धारा-370 खत्म किया और इस साल पांच अगस्त को ही अयोध्या में भव्य राममंदिर की आधार शिला रख दी, इसीलिए देश की आवाम अब अगले साल (2021) के पांच अगस्त का अभी से बेसब्री से इंतजार करने लगा है, संभव है उस दिन भी कोई नया इतिहास बने?

जम्मू-कश्मीर से धारा-370 खत्म करने के साथ ही मोदी सरकार ने देश का एक विशेष समुदाय में सदियों से चली आ रही तीन तलाक की कुप्रथा भी एक झटके में खत्म कर दी और इस समुदाय की महिला वर्ग को एक श्राप से मुक्ति प्रदान करवा दी। इसके साथ ही एन.आर.सी. (राष्ट्रीय नागरिक संहिता) तथा सी.ए.ए. (नागरिकता संशोधन कानून) लागू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए, क्योंकि विदेशों से भारत में आने वालों की यह समस्या कई बरसों से चली आ रही थी, जिसे अब कानूनी जामा पहनाकर उसके नए नियम लागू कर दिए गए। इससे हमारे देश को एक बहुत बड़े झंझट से मुक्ति मिल गई।

अब मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य शेष रह गया है और वह है देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में पिछली कई शताब्दियों से विभिन्न वर्गों के नागरिकों में कई तरह के सामाजिक रीति-रिवाज चल रहे है, जैसे उदाहरण के लिए विवाह प्रथा। हमारे देश में नागरिकों के एक वर्ग को जहां एक ही विवाह करने की बंदिश लागू है, वहीं एक अन्य वर्ग के नागरिकों को चार विवाह तक करने की स्वतंत्रता है, इसी तरह सम्पत्ति व उत्तराधिकार वाले मामले में भी बेटे-बेटियों के बीच मतभेद जारी है, ये तो कुछ ही उदाहरण है, इनके अलावा भी कई ऐसे सामाजिक नियम-कायदे है, जो नागरिकों के बीच मतभेद कायम करते है, इसलिए मोदी सरकार पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान सामाजिक नियम-कायदे कानूनी रूप से स्थापित करना चाहती है और इस विचार को समान नागरिक संहिता के माध्यम से मूर्तरूप देने के प्रयास किए जा रहे है।

ऐसा लगता है कि मोदी सरकार आगामी एक-दो महीनों में ही इस मुद्दें को कानूनी रूप देकर फिर देश की अन्य आर्थिक, रोजगार, औद्योगिक व अन्य समस्याओं से दो-चार होगी और फिर इनसे निपटने में सरकार को इसलिए भी जल्दी नहीं है क्योंकि राममंदिर, तीन तलाक, धारा-370 जैसे महत्वपूर्ण फैसलों से यह सरकार 'दीर्घायू' जो हो गई है और अब तो प्रतिपक्षी दल भी इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे है, ऐसा लगता है कि मध्यप्रदेश की पुण्य नगरी उज्जयिनी में 2028 में होने वाला अगला सिंहस्थ महाकुम्भ मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही सम्पन्न होगा।

अपनेपन की छाप दिखती नई शिक्षा नीति में

सोनम लववंशी, लेखिका

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जमाना हमारा।।मशहूर शायर इकबाल की ये पंक्तियां भारतीय परिवेश और हमारे गौरवशाली इतिहास पर एक दम सटीक बैठती है। यूं तो हमारी पुरातन संस्कृति को खण्ड-खण्ड करने की औछी राजनीति सदियों से ही चली आ रही है। फिर बात चाहे मुगलों की हो या फिर अंग्रेजों की ही क्यों न हो, लेकिन न तो कोई हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटा सका और न ही हमारी परम्पराओं को बदल सका है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना सदियों से हमारी रगों में बहती रही है। ये हमारे संस्कार ही है कि हमने दुनिया को बाजार की नजरों से नहीं बल्कि हमारे अपने परिवार की तरह ही देखा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने ही चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि और पाणनी जैसे कई विद्वानों को पैदा किया है। जिन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान,सर्जरी और सिविल इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका निभाई है। उसी का परिणाम है कि वर्तमान समय में आधुनिक विश्व में जिस प्रकार का कोहराम मचा है उसमें भारत की प्राचीन संस्कृति संपदा का सिक्का बोलता है।

कहते है कि किसी देश की तरक्की सिर्फ उस देश के संसाधनों से नहीं होती है। बल्कि देश की तरक्की में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा मानव में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। हमारे वेदों और उपनिषदों में भी शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि, ष्सा विद्या विमुक्तये।ष् विद्या वह है जो हमें बुद्धि प्रदान करें। किसी भी देश को बनाने और बिगाड़ने में शिक्षा बहुत अहम होती है। अंग्रेजों ने इस बात को बखूबी समझा। इसीलिए लार्ड मैकाले ने 1934 में भारत के लिए शिक्षा पद्धति बनाई। जिसके बारे में मैकाले ने कहा था कि वह जो शिक्षा पद्धति लागू कर रहे है उसका पाठ्यक्रम देखने में तो हिंदुस्तानी लगेगा लेकिन उनका मस्तिष्क अंग्रेजियत हो जाएगा। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का एक ऐसा जहरीला विष है जिसका जहर अब तक हमारी शिक्षा पद्धति में भरा हुआ है। अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण करके ही शिक्षा पद्धति बनाई थी। जिससे भारत को गुलाम बनाकर रखा जा सके। आज उसी का परिणाम है कि हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगार सर्जन करने में नाकामयाब है। अब तक हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे है वह मात्र रटन्त विद्या पर ही आधारित रही है।

एएसईआर की एक रिपोर्ट में कहा गया की हमारे देश में पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले 50 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा की पुस्तक भी नहीं पढ़ पाते है। रिपोर्ट बताती है कि 72 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा के सवाल भी हल नही कर पाते है। वही एम्प्लायमेंट सर्वे के अनुसार 80 फीसदी इंजीनियर किसी नौकरी के योग्य नही है। ऐसे में कैसे मान ले कि छात्रों को डिग्री देने मात्र से ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। यही वजह है कि हमारी शिक्षा पद्धति हमेशा सवालों के घेरे में रही है। देश की आजादी के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया था लेकिन ये परिवर्तन हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई खास बदलाव नही कर पाए। यही वजह है कि आज फिर करीब 34 साल के बाद पुनः एक नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। यूँ तो इस शिक्षा नीति में कई क्रांतिकारी परिवर्तन की बात की गई है। जिसकी शुरुआत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वैसे यह सही भी है क्योंकि मानव को किसी संसाधन के रुप में देखना गलत ही है। शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की बात की गई है। साथ ही नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा भी है कि - निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति की मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के शूल।।

नई शिक्षा नीति में यूं तो कई क्रांतिकारी परिवर्तनों की बात की गई है, लेकिन वास्तविक धरातल पर ये शिक्षा नीति क्या रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा? हाँ एक बात तो है कि इस शिक्षा नीति को ऐसा तैयार किया गया है जिससे वह मैकाले की परिधि से बाहर आ सकें। देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकें।

भय बिन होय न प्रीति

लेखक-वीरेन्द्र सिंह परिहार

स्वामी विवेकानन्द ने बहुत पहले कह दिया था- मैं लोहे की मांसपोशियां एवं फौलाद की नसों वाला मनुष्य चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनं' यानी धर्म की साधना या कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए शरीर ही माध्यम है। कहा जाता है, कि जो अपनी मदद करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं, यानी ईश्वर दुर्बलों के लिए नहीं हैं।

5 अगस्त को अयोध्या में राममंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोस्वामी तुलसीदास की एक लाइन को उद्धधत किया था- 'भय बिन होय न प्रीति।' मोदी द्वारा उपरोक्त बात को कहे जाने पर समीक्षकों द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि सर्वप्रथम तो यह चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्रों के सन्दर्भ में हैं, और दूसरे यह देश में आतंकवादियों, अलगाववादियों और गजवा-ए-हिन्द का सपना देखने वालों के लिए है। दुनिया का इतिहास यह बताता हैं कि दुनिया में युद्धों या हिंसा का एक बड़ा कारण शक्ति-संतुलन का अभाव हैं, क्योंकि जब एक राष्ट्र शक्तिशाली होता हैं, और दूसरा कमजोर होता हैं तो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र को कमजोर राष्ट्र को हड़पने या दबाकर रखने की प्रवृत्ति पैदा होती है। यह बात सिर्फ राष्ट्रों के संदर्भ में ही नही, बल्कि समुदायों के परिप्रेक्षय में भी देखी जाती हैं जैसा कि कभी महात्मा गांधी ने कहा था- 'औसतन एक मुसलमान गुंडा होता हैं और एक हिन्दू भीरू या कायर।' इसीके चलते अंग्रेजों के समय भी हिन्दूओं पर मुस्लिमों द्वारा आक्रमण होते थे, जिससे उन्हे जान-माल का बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। मोपला- विद्रोह इसका एक बड़ा उदाहरण हैं। देश कि आजादी के वक्त मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की वजह से अकेले कलकत्ता शहर में ही छरू हजार हिन्दू मारे गए थे। यह प्रवृत्ति अभी तक जीवित हैं, तभी तो स्वतंत्र भारत में भी आतंकवादी एवं अतिवादी जहाँ पर हिन्दू अल्पसंख्यक है, वहाँ उन पर अत्याचार करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इन दिनों पश्चिम बंगाल हैं, जहाँ सीमा से लगे छरू हजार गांव हिन्दूविहीन हो चले हैं। इसके संबंध में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक पूज्य गुरूजी ने एक जगह लिखा हैं- आखिर में बकरे की बलि ही क्यों दी जाती हैं, शेर की बलि क्यों नही ? इस संबंध में उन्होंने लिखा हैं कि एक बार बकरे ने ब्रम्हाजी से सवाल किया कि आखिर में मेरी ही बलि क्यों दी जाती है ? और लोग बकरे को ही मारकर क्यों खाते हैं ? इस पर ब्रम्हाजी ने कहा कि कमजोर होना सबसे बड़ा अभिशाप है। यहाँ तक कि तेरी निर्बलता और अशक्तता देखकर मुझे ही तुझे खाने की इच्छा पड़ रही है। कहने का आशय यह कि कमजोर होना सिर्फ आततायी या दुष्ट के उत्पीड़न का शिकार ही नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सामान्य लोगो का भी होना पड़ सकता है, क्योंकि कमजोर या निर्बल होने से सामने वाले की मनोवृत्ति ही हड़पने या निगलने की हो जाती है। यानी यदि हम निर्बल हैं, कमजोर हैं तो अशान्ति को, आक्रमण को आमंत्रित करने को स्वतरू जिम्मेदार हैं। यह बात हम राष्ट्र जीवन, समाज जीवन और व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी देख सकते हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने बहुत पहले कह दिया था- ÷मैं लोहे की मांसपोशियां एवं फौलाद की नसों वाला मनुष्य चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनं' यानी धर्म की साधना या कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए शरीर ही माध्यम है। कहा जाता है, कि जो अपनी मदद करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं, यानी ईश्वर दुर्बलों के लिए नहीं हैं। तभी तो कहा गया कि 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यरू' यानी कि शक्तिहीन, कमजोर व्यक्ति आत्मा या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। सच्चाई यह है कि कायर को न इस लोक में कुछ प्राप्त होता है न परलोक में ही। इसी को दृष्टिगत रखते हुए श्री गुरूजी ने कहा था- ÷प्रथम वस्तु है अजेय शारीरिक शक्ति। हमे इतना शक्तिशाली होना है कि सम्पूर्ण संसार में हमे कोई भी न तो विजित कर सके और न अभिभूत कर सके। इसके लिए हमें सशक्त एवं स्वस्थ्य शरीर चाहिए। हमारे सभी अवतार जिन्होंने मानव शरीर धारण किया, इसी प्रकार के थे।÷ हमारे शास्त्रों का सार भी यही रहा है कि शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। यह मोदी के भय का ही परिणाम था कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश में आतंकियों द्वारा कहीं भी बम-विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वह ऐसा करके किसी तरह बचने वाले नहीं हैं। लेकिन शक्तिशाली होने का तात्पर्य सिर्फ शारीरिक शक्ति भर से नहीं है, यदि हममें मानसिक शक्ति नहीं है, आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है, तो मात्र शारीरिक शक्ति या बड़ी सेना का कोई अर्थ नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते छोटी संख्या की सेनाओं ने बड़ी फौजो को हरा दिया। विश्व रंग-मंच पर जब हम इजरायल को देखते हैं, तो पाते हैं कि बहुत छोटा देश होते हुए भी अपने आत्मबल, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह बड़ी संख्या में अरब राष्ट्रो को आए दिन नाको चने चबाता रहता है। पर शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के साथ गुरूजी के अनुसार चारित्रिक एवं अनुशासन की भी शक्ति होनी चाहिए।

कुल मिलाकर मोदी जब उक्त चौपाई का उद्धरण दे रहे थे, तब उसके माध्यम से वह देश को बहुत कुछ बता रहे थे। वह यह भी बता रहे थे कि चूँकि हम नख-दंत विहीन थे, इसलिए चीन को हमसे कोई भय नहीं रहा। 1950 से लेकर 1962 तक हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई तैयार नहीं की और पं0 नेहरू मात्र पंचशील और 'हिन्दी-चीनी, भाई-भाई' का राग अलापते रहे। फलतरू हमारी शक्तिहीनता के चलते चीन द्वारा पहले तिब्बत हड़पा गया फिर भारत पर हमलाकर हमारी 38 हजार वर्ग कि.मी. जमीन हड़प ली गई। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी ही स्थितियों के चलते दो बार खुला आक्रमण करने का साहस किया। चीन आज जो सीमाओं पर गर्जन-तर्जन कर रहा है, उसका कारण यही कि वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हम ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसी स्थिति में एक ही समाधान है कि हमारा देश भी अधिक से अधिक शक्तिशाली बने। इसीको मद्देनजर रखकर देश में नए-नए आधुनिकतम संघारक हथियार मंगाए जा रहे हैं। देश का मनोबल और दृढ़ इच्छा शक्ति तो 2017 में डोकलाम प्रकरण में ही दिख गई थी, पर अब और परवान चढ़ गई है। अतएव मोदी के कहने का आशय यही है, कि पूरे देश को जन-जन को पूरे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एकता और अनुशासन की शक्ति जुटाने पर कोई भी देश हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसे अंततरू मित्रवत व्यवहार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। स्वामी विवकानन्द ने इसीलिए गीता पढ़ने के बजाय फुटबाल खेलने पर जोर दिया था, क्योंकि शक्तिशाली होने पर ही हम गीता के सार को जीवन में उतार सकते है। तभी तो वह जोर देते थे कि- ÷भारत में विश्वास करो, भारतीय धर्म में विश्वास करो, शक्तिशाली बनो, आशावान बनो, संकोच छोड़ो।÷ हमारे उपनिषद भी कहते हैं- ÷हे मानव तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। काम करते हुए 100 वर्ष जीओ।÷ इसीलिए वर्ष में नवदुर्गा के दिनों में हम शक्ति की देवी की उपासना करते हैं। अंततरू इन सबका निष्कर्ष यही- 'भय बिनु होय न प्रीति।'

ट्रंप की टोपी में मोरपंख और बिच्छू

लेखक-डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पिछले दो दिनों में अमेरिका एक बार उठ गया और एक बार गिर गया। वह उठा तब जबकि इस्राइल और संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) में समझौता हो गया और वह गिरा तब जबकि सुरक्षा परिषद में वह ईरान के विरुद्ध बुरी तरह से पछाड़ खा गया। इस्राइल की स्थापना 1948 में हुई लेकिन पश्चिम एशिया के राष्ट्रों में से सिर्फ दो देशों ने अभी तक उसे कूटनीतिक मान्यता दी थी। एक मिस्र और दूसरा जोर्डन। ये दोनों इस्राइल के पड़ौसी राष्ट्र हैं। इन दोनों के इस्राइल के साथ जबर्दस्त युद्ध हुए हैं। इन युद्धों में दोनों की जमीन पर इस्राइल ने कब्जा कर लिया था लेकिन 1978 में मिस्र ने और 1994 में जोर्डन ने इस्राइल के साथ शांति-संधि कर ली और कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिये। इस्राइल ने मिस्र को उसका सिनाई का क्षेत्र वापस किया और जोर्डन ने पश्चिमी तट और गाजा में फलस्तीनी सत्ता स्थापित करवाई लेकिन संयुक्त अरब अमीरात याने अबू धाबी के साथ इस्राइल का जो समझौता हुआ है, उसमें इस्राइल को कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ा है। अबू धाबी इसी बात पर राजी हो गया है कि इस्राइल ने उसे आश्वस्त किया है कि वह पश्चिमी तट के जिन क्षेत्रों का इस्राइल में विलय करना चाहता था, वह नहीं करेगा। इस समझौते का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार ले रही है, जो वाजिब है। उसने ईरान के विरुद्ध इस्राइल, सउदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि कई सुन्नी देशों का एक सम्मेलन पिछले साल पोलैंड में बुलाया था। उसी में इस्राइल और अबू धाबी का प्रेमालाप शुरु हुआ था। इस समझौते से ईरान और तुर्की बेहद खफा हैं लेकिन ट्रंप अपने चुनाव में इसका दोहन करना चाहते हैं। ट्रंप की टोपी में यह एक मोरपंख जरुर बन गया है।

लेकिन सुरक्षा परिषद ने ट्रंप की लू उतारकर रख दी है। अमेरिका ने ईरान पर लगे हथियार खरीदने के प्रतिबंधों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन 15 सदस्योंवाली इस सुरक्षा परिषद में सिर्फएक सदस्य ने उसका समर्थन किया। उसका नाम है- डोमिनिकन रिपब्लिक। यह एक छोटा-सा महत्वहीन देश है। अमेरिका को ऐसी पराजय का मुंह पिछले 75 साल में पहली बार देखने को मिला है। यों भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और कमला हैरिस के जीतने के आसार इतने बढ़ गए हैं कि दुनिया के राष्ट्र बड़बोले ट्रंप का ज्यादा लिहाज नहीं कर रहे हैं। चीन ने हाल ही में ईरान के साथ अरबों डॉलर खपाने का समझौता किया है और रुस के व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ हुए अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते पर एक शिखर सम्मेलन बुलाने का भी सुझाव दिया है। ट्रंप की टोपी में ईरान एक बिच्छू बना हुआ है।

आपदा में अवसर का उदाहरण

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर का सूत्र दिया था। इसपर क्रियान्वयन हेतु अबतक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके प्रति सजग रहे हैं। वह केंद्र की सभी कल्याणकारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करते हैं। इसके सार्थक परिणाम भी हुए। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना कालखण्ड में सेवा के साथ-साथ अपने विकास कार्यों के माध्यम से देश और दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। जहां पूरी दुनिया में कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, वहीं उत्तर प्रदेश में इस वर्ष जुलाई माह में विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति मात्र तीन प्रतिशत कम है।

इसका मतलब है कि कोरोना से लड़ते और बाढ़ से जूझते हुए भी राजस्व प्राप्ति की ओर पूरी तरह से अग्रसर हैं। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे व मेट्रो के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया गया है। आजादी के बाद से वर्ष 2016 तक केवल बारह मेडिकल कॉलेज ही उत्तर प्रदेश में थे। विगत तीन वर्षों के दौरान 19 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य व दो नए एम्स का निर्माण प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में दो करोड़ इकसठ लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया गया। तीस लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ जरूरतमंदों को प्राप्त हो रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा तीन लाख नौजवानों को बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी देने का कार्य किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश भी तेजी से प्रयास कर रहा है।

कोरोना कालखण्ड में प्रधानमंत्री ने एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना को प्रारम्भ किया। इसके माध्यम से अस्सी करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अठारह करोड़ लोगों को अनवरत महीने में दो बार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रमिकों, स्ट्रीट वेण्डरों, गरीब, प्रवासी कामगारों-श्रमिकों को खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करावाने का कार्य किया गया है। स्वदेशी और स्वाबलम्बन के महत्व के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक

उत्पाद योजना को आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में एक उत्पाद को चिन्हित कर उसकी ब्राण्डिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग और उसको तकनीक के साथ जोड़कर वैश्विक बाजार में उसे आगे बढ़ाने का कार्य मजबूती से हुआ है।

लॉकडाउन के दौरान चालीस लाख कामगार श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस लौटे थे। उनके लिये क्वारंटीन सेण्टर व शेल्टर होम्स के निर्माण किया गया। वापस लौटे श्रमिकों के लिए बहुत कम अवधि में जनसहभागिता के आधार पर ग्रामीण इलाकों में साठ हजार निगरानी समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने क्वारंटीन व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने में उपयोगी योगदान किया। बहुत कम समय में अस्पतालों में डेढ़ लाख से अधिक कोविड बेड का प्रबन्ध किया गया। लॉकडाउन के दौरान प्रदेशवासियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था की गयी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी से गरीबों व वापस लौटे श्रमिकों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया। प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे, इस भावना व संवेदनशीलता से राज्य सरकार ने कार्य किया। पन्द्रह करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न का प्रबन्ध किया गया। इसके लिए प्रदेश की गरीब जनता में बयालीस लाख मीट्रिक टन राशन वितरित किया गया। राशन कार्ड न होने पर भी गरीबों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उत्तर प्रदेश के लगभग सवा तीन करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पांच हजार करोड़ रुपये की धनराशि अंतरित की गयी। आजादी के बाद के इतिहास में आजतक सम्भवत: किसी सरकार ने गरीबों की ऐसी मदद नहीं की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में भी उत्तर प्रदेश आगे है। आवास योजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पंचायत भवन, तालाब निर्माण, इण्टरनेट की लाइनों के बिछाने आदि कार्यों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने लगभग सवा करोड़ श्रमिकों कामगारों को रोजगार दिया गया। पचास लाख लोगों को एमएसएमई इकाइयों में रोजगार दिया जा गया। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब दस हजार करोड़ रुपये का ऋण आवंटित किया गया है। ऋण के साथ हजारों हस्तशिल्पियों को आधुनिक मशीनें और उनके काम के लिए आवश्यक टूल किट भी दी गयी है। सवा करोड़ कामगारों की पहचान करना, तीस लाख से ज्यादा श्रमिकों के कौशल व अनुभव का डेटा तैयार करना और उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था करना साधारण कार्य नहीं था।

एक जनपद एक उत्पाद योजना में प्रदेश में पहले से ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत कुछ दिन पहले दो लाख अड़सठ हजार इकाइयों को साढ़े छह हजार करोड़ रुपये का ऋण, एक लाख पैंतीस हजार नई इकाइयों को चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना व एक जनपद, एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत पांच हजार से अधिक उत्तर प्रदेश के परम्परागत कारीगरों को टूल किट का वितरण हुआ। महिला कामगारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। अनलॉक के बाद लगभग सात लाख अस्सी हजार औद्योगिक इकाइयों संचालित की गयीं। आत्मनिर्भर भारत योजना के पहले चरण में प्रदेश में लगभग सत्तावन हजार नई एमएसएमई इकाइयों को दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया। इन इकाइयों द्वारा कार्य का संचालन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

राह भटकती कांग्रेस

रमेश सर्राफ्धमोरा

कभी देश पर एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी मौजूदा समय में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस राह भटक गई हो। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का गंभीर संकट है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले एक साल से सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। सोनिया गांधी का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक साल का कार्यकाल भी 10 अगस्त को पूरा हो चुका है। लेकिन अभीतक कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष का चुनाव करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है।

कांग्रेस पार्टी में जबतक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तबतक पार्टी में नेतृत्व का संकट रहेगा। सोनिया गांधी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष तो हैं मगर उम्र के हिसाब से वह अधिक भागदौड़ में सक्षम नहीं हैं। ऊपर से प्रदेशों में लगातार नेतृत्व का संकट पैदा हो रहा है। कहने को तो कांग्रेस में हर काम आलाकमान की सहमति से किया जाता है मगर आलाकमान में कौन-कौन नेता शामिल हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। पहले कांग्रेस कार्यसमिति सबसे प्रभावशाली व महत्वपूर्ण होती थी। कार्यसमिति में लिया गया निर्णय अंतिम होता था। मगर मौजूदा समय में कांग्रेस कार्यसमिति की भूमिका सीमित हो गई है। कार्यसमिति में ऐसे नेताओं की बहुलता है जिनको चुनाव लड़े जमाना बीत गया है। जो वर्षों से राज्यसभा के रास्ते संसद में आते रहे हैं। इस कारण उन नेताओं का आम जनता में प्रभाव समाप्त हो गया है। कार्यसमिति में शामिल अधिकांश नेता अपने परिवार जनों को भी राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। इस कारण नई पीढ़ी के उन नेताओं से उनका टकराव बना रहता है जो मेहनत करके सांगठनिक क्षमता से आगे बढ़े हैं।

कांग्रेस में आज युवा व पुराने नेताओं के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने देश के बहुत से युवा नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में काम करने का मौका देकर उन्हें आगे बढ़ाया था। उस दौरान कांग्रेस में काफी सक्रियता भी देखी गई थी। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कांग्रेस के सभी नेताओं ने उनको अध्यक्ष पद पर बने रहने की काफी कोशिश की थी मगर राहुल गांधी अपने फैसले पर अडिग रहे। अंततः सोनिया गांधी को ही 10 अगस्त 2019 को एक वर्ष के लिए कांग्रेस का अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद पुराने नेताओं का फिर से पार्टी में बोलबाला हो गया। इसी कारण राहुल गांधी के समय आगे बढ़ाए गए युवा नेताओं को पुराने नेताओं ने एक-एक ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर, संजय निरुपम, सचिन पायलट, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय झा जैसे नेताओं को धीरे-धीरे साइड लाइन किया जाने लगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ व दिग्विजय सिंह की मनमानी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ा। उनके साथ उनके समर्थक 22 विधायकों ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस कारण मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई। वहां डेढ़ साल बाद ही फिर से भाजपा के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। इससे पूर्व यही स्थिति कर्नाटक में दोहराई गई थी। जहां भी भाजपा के येदियुरप्पा फिर से मुख्यमंत्री बन गए। दोनों ही जगह पार्टी के स्थानीय नेतृत्व से नाराज लोगों की पार्टी आलाकमान ने बात नहीं सुनी। वहां प्रादेशिक नेतृत्व को एकतरफा छूट दी गई। जिस कारण असंतुष्ट नेताओं को लगने लगा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस कारण उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना उचित समझा। मध्य प्रदेश व कर्नाटक कांग्रेस में जो कुछ घटा उसके लिए वहां के प्रभारी महासचिव भी पूरी तरह जिम्मेदार थे। जिन्होंने असंतुष्ट गुट के नेताओं की बातों को न तो सुना और न ही उसका समय रहते कोई समाधान निकाला। प्रभारी महासचिव सिर्फप्रदेश के मुख्यमंत्री को ही खुश करने में लगे रहे। उनकी बातों पर ही एकतरफा फैसला करते रहे।

हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद वहां के प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया को हटाकर मुकुल वासनिक को महासचिव बनाया गया है। लेकिन अब मुकुल वासनिक भी कुछ नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसे केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाही व प्रादेशिक नेताओं की मनमानी के चलते मात्र डेढ़ साल में गिरा दिया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक लगातार त्यागपत्र दे रहे हैं। जिससे वहां कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है।

मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी उप मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने अपने समर्थक 18 विधायकों को लेकर पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। उनका भी यही आरोप था कि मुख्यमंत्री उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे दिल्ली आलाकमान में सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही पैरवी करते हैं। इस कारण उन्होंने पार्टी में अपनी लगातार हो रही उपेक्षा के चलते अपने समर्थक 22 अन्य विधायकों को लेकर गुड़गांव चले गए। उनका कहना था वे कांग्रेस में हैं और कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी कांग्रेस से नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से असहमति है। हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हमें मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा है। उन्होंने प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया। यह तो अच्छा रहा कि एक महीने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दखल के बाद राहुल गांधी व सोनिया गांधी से सचिन पायलट व उनके समर्थक विधायकों की मुलाकात करवाकर रूबरू बात करवाई गई। जिसपर सोनिया गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मुख्यमंत्री गहलोत से जो भी शिकायतें हैं उन सबको दूर करवाया जाएगा। राजस्थान प्रकरण के समाधान के लिये दिल्ली से तीन वरिष्ठ नेताओं की एक समिति बनाई जाएगी जो वहां के सभी मुद्दों को सुलझायेगी। इसके बाद सचिन पायलट जयपुर आकर विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुए। यहां प्रश्न उठता है कि पार्टी की भारी फजीहत होने के बाद प्रियंका गांधी ने जो काम एक महीने बाद किया, उसे पहले भी किया जाता जा सकता था। उसके अलावा दिल्ली से संकट को निपटाने के लिए भेजे गए पार्टी पर्यवेक्षक प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। उन्होंने जयपुर आकर प्रेस के माध्यम से पायलट को पार्टी से निकालने की चेतावनी देते रहे। वे सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रवक्ता की तरह काम करने लगे। जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। कांग्रेस आलाकमान को चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे ऐसे लोगों को पद मुक्त करें जो निष्पक्षता से काम नहीं कर किसी प्रभावशाली नेता के पैरोकार के रूप में काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय स्तर पर एक ऐसी प्रभावशाली कमेटी बनानी चाहिए जो ऐसे मुद्दों पर समय रहते ध्यान देकर उनका निदान करवा सके। प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारी पद पर ऐसे लोगों को लगाया जाये जो निष्पक्षता से काम करने वाले हों। उनकी कार्यप्रणाली की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिये। ताकि वो अपनी मनमानी नहीं कर सके व कांग्रेस को बार-बार अपने नेताओं की बगावत का सामना नहीं करना पड़े।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

फेसबुक की निष्पक्षता पर सवाल

प्रमोद भार्गव

अमेरिका के दैनिक अखबार द वॉल स्ट्रीट जनरल् ने फेसबुक की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अखबार के अनुसार, श्सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भाजपा नेताओं और कुछ समूहों के हेट स्पीच, मसलन नफरत फैलाने वाली पोस्टों के खिलाफन तो कोई जान-बूझकर कार्यवाही की और न ही उन्हें हटाया। भारत में फेसबुक से जुड़ी नीतियों के निदेशक आंखी दास ने भाजपा नेता एवं तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह के खिलाफहेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था। उन्हें डर था कि इससे फेसबुक से भाजपा के संबंधों में खटास आ सकती है। नतीजतन कारोबार प्रभावित हो सकता है।श् हालांकि अखबार में कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान फेसबुक ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तानी सेना, भारतीय कांग्रेस और भाजपा से जुड़ी अप्रमाणिक खबरों को फेसबुक पेज से हटा दिया है। जबकि हकीकत यह है कि आपत्तिजनक कुछ खबरें अभी भी पड़ी हुई हैं।

इस खबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तुरंत लपकते हुए कहा कि श्भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में फेसबुक और वाट्सअप को नियंत्रित करते हैं और इनके जरिए फर्जी व नफरत फैलाने वाली खबरों को डालकर मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है। आखिरकार अमेरिकी मीडिया फेसबुक को लेकर सच्चाई के साथ सामने आया है।श् राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा कि श्जो नेता अपनी ही पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, ऐसे हारे हुए दावा कर रहे हैं कि भाजपा और संघ दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। जबकि लोकसभा चुनाव से पहले यूजर्स के डेटा को हथियार बनाने के लिए इन्हीं को कैंब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।श् वॉल स्ट्रीट की खबर और उस पर राहुल की प्रतिक्रिया नादानी के कुछ इस तर्ज पर दिए उदाहरण हैं कि कौआ कान भी काट ले गया और पता भी नहीं चला। जिन राजा सिंह की खबर को तूल दिया गया है, वे भाजपा के ऐसे कद्दावर नेता नहीं हैं कि उनकी खबरें एक बड़े समुदाय को प्रभावित कर सके। लिहाजा यह खबर प्रथम दृष्टि में तो यही लगती है कि इसे भाजपा और संघ को बदनाम करने के नजरिए से प्रकाशित किया गया है।

अलबत्ता इतना सही है कि भारत में फेसबुक के दुनिया में सबसे ज्यादा 28 करोड़ यूजर्स हैं और वह इन्हें प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भारतीय उदारता के चलते अपने लाभ के लिए यूजर्स के डेटा का मनचाहा उपयोग करने के आरोप भी फेसबुक पर लगते रहे हैं। इसीलिए यूरोपीय महासंघ की सर्वोच्च अदालत ने फेसबुक और गूगल द्वारा यूरोप से अमेरिका को डेटा हस्तांतरित करने पर रोक लगाई हुई है। किंतु हमारे यहां जुकरबर्ग द्वारा सरकारी दस्तावेजों समेत प्रयोगकर्ताओं की सभी सूचनाएं, मसलन चित्र, वीडियो, अभिलेख, साहित्य जो भी बौद्धिक संपदा के रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें किसी को भी हासिल कराने का अधिकार प्राप्त है। इन जानकारियों को कंपनियों को बेचकर फेसबुक खरबों की कमाई कर रहा है। इन्हीं सूचनाओं को आधार बनाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार को अपनी मुट्ठी में ले रही हैं। इसके अलावा हरेक खाते से फेसबुक को औसतन सालाना 10,000 रुपए की आमदनी होती है। फेसबुक के अलावा वाट्सअप पर भी 16 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय ग्राहक हैं। किंतु ये भारत में आयकर और सेवाकर से मुक्त हैं। फिलहाल तो फेसबुक के पास भारत के आयकर विभाग का पेन नंबर भी नहीं है। दरअसल फेसबुक के पास श्कुकीजश् नामक ऐसी फाइलें होती हैं, जो इंटरनेट यूजरों पर निगाह रखती हैं कि एक यूजर किस वेबसाइट पर गया और उसने क्या सूचना दर्ज कराई और किस अन्य वेबसाइट को साझा की। ये फाइलें यह भी नजर रखती हैं कि किस पेज पर कितना समय यूजर ने किसके साथ बिताया। मसलन फेसबुक व्यक्तिगत व सामूहिक जासूसी का बड़ा माध्यम है। निगरानी की इसी वजह से बेल्जियम की एक अदालत ने फेसबुक पर 2.50 लाख यूरो का जुर्माना लगाया था। साथ ही फेसबुक को बाध्य किया था कि लोगों की सूचनाएं एकत्र करने के लिए फेसबुक को उपयोगकर्ता से अनुमति लेनी होगी।

रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक और कैंबिज्र एनालिटिका के गठजोड़ को डेटा के इस्तेमाल का कांग्रेस पर जो आरोप लगाया है, वह 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। दरअसल इस चुनाव के पहले ब्रिटिश चौनल-4 के स्टिंग के माध्यम से खुलासा किया गया था कि चौनल ने कैंब्रिज एनालिटिका के आधिकारियों का स्टिंग कर उनसे काबूलवाया है कि डाटा की बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। यह कंपनी दुनिया भर के राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के दौरान सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यह फर्म हनी ट्रैप, फेक न्यूज जैसे गलत हथकंडे भी अपनाती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपनी बेव प्रोफाइल में दावा किया है कि 2010 में उसने भारत के बिहार में और 2017 में गुजरात तथा पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की मदद की थी। भारत में कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम एससीएल इंडिया से जुड़ा है। इसके बेव ठिकाने के मुताबिक यह लंदन के एससीएल समूह और ओवलेनो बिजनेस इंटेलिजेंस का साझा उपक्रम है।

यदि वाकई फेसबुक ने किसी दूसरे देश की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर जनमत को प्रभावित करने की शक्ति हासिल कर ली है तो यह राजनैतिक दलों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि भारतीय चुनाव के संदर्भ में जो जानकारी सामने आई है, उससे पता चलता है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसे जिन सीटों को प्रभावित कर अनुकूल परिणाम लाने का लक्ष्य दिया गया था, उसमें यह 90 फीसदी सफल रहा था। मसलन जिन उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें से 90 प्रतिशत उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इन्हीं परिणामों के बूते यह कंपनी भारत में 2019 के आम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों से संपर्क में थी। लेकिन चुनाव को प्रभावित करने की खबर मिलते ही रविशंकर प्रसाद ने इस चोरी को गंभीरता से लेते हुए फेसबुक को चेतावनी दी थी कि श्यदि गलत तरीके से भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई तो फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग को भारत तलब किया जाएगा।श् इस चेतावनी से फेसबुक चुनाव को प्रभावित करने की गतिविधियों से पीछे हट गया था।

सोशल मीडिया पर मौजूद बड़े डाटा का चुनाव अभियान में इस्तेमाल भारतीय लोकतंत्र के लिए भविष्य में नया खतरा साबित हो सकता है? आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कई बेव ठिकाने हैं, जिनके पास करोड़ों लोगों की व्यक्तिगत जानकारी है। हालांकि ये साइट्स गोपनीयता का भरोसा देती है, लेकिन फेसबुक पर डाटा चुराकर उसका प्रयोग चुनाव प्रचार में करने का जो पर्दाफाश एनालिटिका ने किया, उसने इस भरोसे को तोड़ने का काम किया है। बावजूद सोशल साइटों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण भारत सरकार का नहीं है।

दरअसल गोरांग महाप्रभुओं के सामने दंडवत होना हमारी पुरानी फितरत है। वह काला अथवा वर्णसंकर हो तो भी हम सरलता से सम्मोहित हो जाते हैं। इस नजरिए से एक नए अवतार के रूप में जुकरबर्ग दो साल पहले भारत में नेट की आजादी छीनने के लिए आए थे। उन्होंने बकायदा 300 करोड़ के विज्ञापन देकर मीडिया को अपने हित में साधने की कोशिश भी की थी। उनकी इस मुहिम में एयरटेल और रिलाइंस जैसी भारतीय कंपनियां भी शामिल थीं। इस विश्वबंधु की दृष्टि हमारी सवा सौ करोड़ आबादी को फ्री बेसिक्स के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं देने से जुड़ी थी। इसके जरिए जुकरबर्ग भारत के इंटरनेट और ई-बाजार पर कब्जा करना चाहते थे। इस नाते उनका इंटरनेट डॉट ओआरजी प्रोजेक्ट भारतीय दूरसंचार विनियामक आयोग के पास लंबित था। जिसे दो टूक फैसला सुनाकर ट्राई ने नकार दिया था। जुकरबर्ग ने चालाकी बरतते हुए ट्राई को अपने पक्ष में ग्राहकों द्वारा वोट के जरिए प्रभावित करने की कोशिश भी की थी। ट्राई

सेंट्रल बैंक कर्मचारियों ने किसान के घर जाकर गाली-गलौज और डरा धमकाकर 40 हजार रुपए लेकर आए, थाने में की शिकायत

माही की गूंज, रतलाम

रतलाम जिले के कालूखेड़ा सेंट्रल बैंक में एक किसान बद्रीलाल कुमावत निवासी झांतला ने मंगलवार दोहपर को 70 हजार रुपए निकालने आया था और पैसे निकालकर अपने घर चला गया। जिसके बाद शाम को लगभग 7 बजे बैंककर्मी किसान बद्रीलाल कुमावत के घर गए और उसे बोला कि, तुमारे पास 40 हजार रुपये ज्यादा आ गए है, जब किसान ने मना बोला कि, मेने 70 हजार निकाले और 70 हजार रुपए ही घर लेके आया हूं, तो बैंककर्मियों द्वारा किसान से गाली गलौज की ओर डरा धमका के उस से 40 हजार रुपए लेके आ गए। जिसके बाद किसान ने थाने में आवेदन दिया और पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला कि, तालिदान की एक महिला 15 हजार निकालने आई थी, तो उसके पास 55 हजार रुपए चले गए थे, महिला द्वारा पुनः बैंक आकर बैंक को रूपए वापिस कर दिए।

किसान बद्रीलाल कुमावत ने बताया कि, मेने बैंक से 70 हजार रुपए निकाले थे मंगलवार शाम को बैंक के 4 से 5 लोग मेरे घर आए और मेरे से बोले कि, तुमारे पास बैंक से 40 हजार रुपए ज्यादा आ गए है, जब मैने बोला कि, मैने जितने रूपए निकाले उतने ही लाया हु, तो बैंक कर्मचारियों ने मेरे साथ गाली-गलौज की ओर मूझे डराया धमकाया ओर मेरे पास से जबरन 40 हजार रुपए लेके चले गए। जांचकर्ता पंकज राजपूत ने बताया कि, बद्रीलाल कुमावत द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि, बैंक कर्मचारी ने मेरे घर पर आकर कहा कि, तुम्हे 40 हजार ज्यादा दे दिए और गाली-गलौज की व डराया धमकाया मैंने डर की वजह से पैसे उन्हें लोटा दिए, जब जांच की तो तालिदाना निवासी एक महिला के पास ज्यादा पैसे चले गए थे, महिला ने पैसे बैंक में आकर लोटा दिए और जो बैंक कर्मचारी द्वारा बद्रीलाल कुमावत से पैसे लिए थे वो सुबह बैंक कर्मचारी लौटाएंगे, बैंक के मैनेजर से बात करना चाही तो, कॉल रिसीव नही किया।

पीओपी निर्मित प्रतिमाओं पर प्रतिबंध का स्वागत

माही की गूंज, सनावद। नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण कस्बो में रासायनिक पदार्थ पीओपी से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध का पर्यावरण प्रेमी नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने व्यापक स्तर पर स्वागत किया है। इसके लिए पूर्व से चलाए जा रहे अभियान को प्रशासनिक सहयोग मिलने से इसके परिणाम अब धरातल पर नजर आ रहे है। पिछले कुछ सालों में धार्मिक पर्व जैसे गणेश उत्सव नवरात्रि पर पीओपी से बनी प्रतिमाओं का चलन बढ़ गया था। रासायनिक पदार्थों से निर्मित प्रतिमाओं के विसर्जन से जल स्त्रोत नदियां आदि का जल प्रदूषित होता है। और जल में निवास करने वाले पर्यावरण मित्र जलचरों को भी हानि पहुंचती है। इसलिए खरगोन जिला प्रशासन द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए पीओपी प्रतिमा के निर्माण पर लगाया गया प्रतिबंध स्वागत योग्य है।

ज्ञात हो कि जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार मूर्तियों के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया जाए। जैसा की पवित्र ग्रंथों में उल्लेखित है। मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत मिट्टी का ही उपयोग किया जाए। मूर्ति निर्माण में पकी हुई मिट्टी, पीओपी या किसी प्रकार के केमिकल व रासायनिक वस्तुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। टीआई ललितसिंह डांगुर ने बताया की नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में आगामी पर्वो पर प्रतिमा निर्माण के लिए जिला प्रशासन के निर्देश का पालन किया जाएगा। वहीं विक्रय की जाने वाली मूतियों का निर्माण की ऊंचाई अधिकतम 2 फीट की रहेगी। इससे अधिक ऊंचाई की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाए और न ही विक्रय की जाएं। पूजन सामग्री जैसे फल-फूल, नारियल, वस्त्र-आभूषण, सजावट के सामान, जिनमें कागज व प्लॉस्टिक की निर्मित वस्तुएं शामिल है, को मूर्तिध्प्रतिमाओं विसर्जन के पूर्व निकाल कर उन्हें अलग-अलग एकत्रित करें। मूर्ति के विसर्जन के 24 घंटे के भीतर विसर्जित मूर्ति से उत्पन्न ठोस अपशिष्टों जैसे बांस, रस्सी, मिट्टी, पीओपी, प्रतिमा के हिस्से आदि को एकत्रित कर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम-2000 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेश 11 अगस्त से 14 अक्टूबर 2020 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। टीआई डांगुर ने बताया कि धार्मिक आयोजनों के सबंध में स्थानीय आयोजन समिति की बेठक कर जिलास्तर पर मिले निर्देशो का पालन करने की बात बता दी गई है। साथ ही आयोजनों के दौरान प्रशासन के मापदंडों का पालन नही करने पर आयोजको की जवाबदारी रहेगी

संस्कृति मंत्री सुश्री ठाकुर ने बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर की पूजा-अर्चना

माही की गूंज, बैडिया

प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग की मंत्री सुश्री उषा ठाकुर मंगलवार 18 अगस्त को देश के अजेय योद्धा श्रीमंत बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल रावेरखेड़ी पहुंची। यहां उन्होंने श्रीमंत पेशवा की जयंति पर पूजा-अर्चना कर उनकी समाधि स्थल पर कहा कि, खरगोन के इस ऐतिहासिक स्थल का पर्यटन विभाग के कैलेंडर पर विशेष फोटो और इतिहास प्रदर्शित किया जाएगा। श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान समिति ने रावेरखेड़ी पर उनकी पुण्यतिथि 28 अप्रैल को 3 दिनों का मेला और यहां उनके नाम से सैनिक स्कूल खोलने की मांग रखी। संस्कृति मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने समाधि स्थल का अवलोकन कर रमणीय स्थल की प्रशंसा करते हुए पर्यटक स्थल को विकसित करने पर विचार करने की बात कहीं। रावेरखेड़ी स्थित श्रीमंत पेशवा का यह समाधि स्थल सन् 1741 में राणोजी सिंधिया द्वारा बनाया गया था। जयंति अवसर पर श्रीमंत पेशवा के वंशज नूर आलम भी उपस्थित हुए और संस्कृति मंत्री से भेंट की। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष लक्ष्मण इंगले, संरक्षण श्रीपाद कुलकर्णी, उपाध्यक्ष मनोज बिरला, सचिव विवेक भटोरे, सह सचिव नागेंद्र मुछाला, रामेश्वर वार्डिया, जितेंद्रसिंह पाटीदार, सदस्य राजेंद्र साद, जितेंद्र सुराणा पंकज परिहार आदि उपस्थित रहे।

घर-घर विराजित हो मिट्टी के इको फ्रेंडली गणेशा

माही की गूंज, सनावद। इस वर्ष हर घर में मिट्टी के इको फ्रेंडली गणेश जी स्थापित हो इसी उद्देश्य के लिए शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सनावद की शिक्षिका ज्योति भटनागर स्कूल की विभिन्न छात्राओं को घर पर ही मिट्टी के इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। बच्चों को मिट्टी के गणेश जी घर में ही विसर्जित कर प्रकृति के संरक्षण के बारे में बताया।

श्रीमति भटनागर ने बताया कि, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा संकल्प है कि, मिट्टी के गणेश जी स्थापित करें एवं उसका विसर्जन घर के ही बगीचे या किसी जल पात्र में करें। ताकि हमारे जल स्त्रोत एवं पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, इस दिन घर-घर विराजित होंगे गणेश जी।

खुशियों की दास्तां: स्ट्रीट वेंडर योजना का मिला सहारा, राजू बन गया जेंटलमैन

माही की गूंज बड़वानी

पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, जिसके कारण खेलने-कूदने के दिन में उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करना पड़ी। इसका असर यह हुआ कि, वह कक्षा तीसरी के आगे नहीं पढ़ पाया। 10 वर्ष की आयु में बस्ता छोड़कर तगारी उठाने की मजबूरी में 10 वर्ष कैसे गुजर गए यह राजू अहिरवार कभी नहीं समझ पाए। जिस ठेकेदार के पास में काम कर अपनी पत्नी एवं एक बच्चे का जैसे तैसे गुजर-बसर करते थे, कोरोना वायरस की महामारी ने ठेकेदार को ही काम से मोहताज कर दिया। ऐसे में राजू पर क्या गुजरी, इसकी कल्पना से ही शरीर में सिरहन उत्पन्न हो जाती है।

किंतु अब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के कारण राजू अहिरवार के दिन बदलने लगे हैं। योजना के तहत मिले बिना ब्याज के 10 हजार रुपए ने उनकी जिंदगी की रुकी हुई गाड़ी को फिर से चलायमान कर दिया है। वर्षों पूर्व अपने पिताजी की चप्पल-जूते रिपेयरिंग की बंद दुकान को राजू ने पुनः शुरू कर दिया है। योजना से मिली राशि से लाई गई चप्पल-जूते के कारण उनकी ग्राहकी अब बढ़ने लगी है। जिसके कारण राजू अब प्रतिदिन इतनी बचत करने लगा है जो उनको मजदूरी से मिलने वाली राशि से अधिक होती है। जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव का असर यह हुआ कि, अब राजू के दुर्दिन के साथी भी उसे जेंटलमैन के नाम से पुकारने लगे हैं।

कैबिनेट मंत्री का भाजपा नगर मंडल ने किया स्वागत

माही की गूंज, सनावद

प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर रावेरखेड़ी दौरे के दौरान मंगलवार दोपहर 3 बजे सनावद पहुंची। जहां भाजपा नगर मंडल द्वारा खरगोन रोड पर मंत्री ठाकुर का स्वागत किया गया।

मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि सभी लोगों को राम मंदिर निर्माण की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएं साथ ही मंत्रालय का उद्देश्य आम लोगों को संस्कृति व अध्यात्मा से जोड़ना है यह विभाग जन-जन का बने इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूं। इंदौर इच्छापुर हाइवे के सम्बंध में भी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा करुँगी। इस दौरान पूर्व प्रदेश मंत्री ज्योति एवेतिकर, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम पुरोहित, संजय राठौड़, विष्णु ठेकेदार, श्याम महेश्वरी, विजय जैन, निलेश मालाकार, सुकेश जैन, राजा सोनी, कपिल जटाले, मोनू जैन मुख्य रूप से मौजूद थे!

मदिरा के अवैध गोरखधंधे का मामला हुआ उजागर

माही की गूंज, सनावद

सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के निर्देशन में वृत बड़वाह, महेश्वर एवं सनावद आबकारी दल द्वारा संयुक्त रूप से 17 व 18 अगस्त को सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन टिकेकर, के नेतृत्व में वृत-सनावद एवं बड़वाह में अवैध मदिरा आसवन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध वृत सनावद के ग्राम-सताजना, बेड़िया,छोटी बागदा, अम्बा एवं वृत बड़वाह के ग्राम रावत पलासिया, टिटबा पलासिया एवं लोहदरा फाल्या में कार्यवाही कर वृत प्रभारी अजयपाल सिंह भदौरिया एवं मुकेश गौर आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क,च के 10 प्रकरण दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में अलग-अलग स्थानों से 37 पाव देशी मदिरा प्लेन, ,51 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त की एवं 4 हजार 680 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर सेम्पल लेकर विधिवत नष्ट किया। जप्त मदिरा, महुआ लहान एवं मदिरा बनाये जाने के उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 2 लाख 50 हजार रुपए है।

लॉयंस क्लब ने पोधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

माही की गूंज, सनावद। लॉयनेस क्लब की अध्यक्ष अनिता भागचंद जैन ने बालाजी हिल्स परिसर में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जैन ने कहा कि आज वसुंधरा को सबसे अधिक हरियाली की आवश्यकता है। हरी-भरी वसुंधरा से ही मानव जीवन खुशहाल हो सकता है। क्योंकि वृक्ष ही धरती पर वर्षा कराने में मददगार होते हैं और ऋतु परिवर्तन कराते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए जंगल जरूरी हैं। जैन ने नागरिकों से अपने आसपास एक पौधा रोपने की कॉपी की। जैन ने कहा कि पौधा रोपने के बाद पौधे को वृक्ष बनने तक सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है,तभी वृक्षारोपण की सार्थकता है।

जिला दंडाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

माही की गूंज, खरगोन । आगामी त्यौहारों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है, जारी आदेश में उन्होंने कहा कि, समस्त मूर्तियां/प्रतिमाओं तथा अन्य संरचना के निर्माण में केवल प्राकृतिक सामग्रियों का ही निर्माण किया जाए, जैसा कि पवित्र ग्रंथों में उल्लेखित है। निर्माण में मिट्टी का उपयोग किया जाएं। पकी हुई मिट्टी, पीओपी या किसी प्रकार की रासायनिक वस्तुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

परंपरागत मूर्तियों/प्रतिमाओं संरचना का उत्पादन एवं विक्रय जिले में किया जाएं। मूर्तियों की ऊंचाई अधिकतम 2 फीट रहेगी। इससे अधिक ऊंचाई वाली मूर्ति का निर्माण व विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं मोर्हरम के ताजियों की ऊंचाई भी 2 फीट रहेगी। इससे अधिक ऊंचाई वाले ताजियों का निर्माण पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आने वाले समस्त त्यौहारों व पर्वो पर डीजे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 19 अगस्त से 18 अक्टूबर 2020 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा-

बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट, मामले में नामजद झूठा प्रकरण बनाने के आरोप लगाए, ग्रामीणों ने सौपा ज्ञापन

माही की गूंज, पेटलावद

31 जुलाई को ग्राम गोपालपुरा में बिजली के पोल पर चढ़ कर लाईन का काम कर रहे लाइनमैन गजराजसिंह सिसोदिया की मौत के बाद बिजली विभाग पेटलावद में पदस्थ अधिकारी सहायक यंत्री और फीडर प्रभारी द्वारा लाइनमैन की मौत के बाद खुद को बचाने के घटना में लाइनमैन की लापरवाही बताने से नाराज ग्रामीणों से झूमा-झटखी हो गई थी, मोके पर मौजूद पुलिस बल ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल कर थाने पहुँचा दिया था बाद में सहायक यंत्री जितेंद्र कुमार वाघेला द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया गया। सहायक यत्री की रिपोर्ट पर पुलिस ने 6 लोगो को नामजद व अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया था। प्रकरण में नामजद किए गए 6 लोग रूपगढ़ के सिर्वी समाज के है जिनका आरोप है कि, बिजली विभाग पेटलावद के कर्मचारियों ने लाइनमैन की मौत में अपनी लापरवाही छुपाने के लिए मामले को गुमराह करने के लिए झूठा प्रकरण बैकसूरों के विरुद्ध बनवा दिया।

निष्पक्ष जाँच की मांग

मामले में नामजद आरोपित लोगो के परिवारजनों और ग्रामीणों ने एसपी और सांसद को ज्ञापन देकर मामले की जाँच करने की मांग की है।

मामले में नामजद जिन व्यक्तियो के विरूद्ध मामला दर्ज करवाया है उनके परिवार वालो ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ज्ञापन में मामले की जाँच की मांग करते हुए बताया कि, बिजली विभाग के लाइनमैन द्वारा लाईन सुधारने का कार्य किया जा रहा था और बिजली विभाग के जबबदारो ने लापरवाही बरते हुए बिजली शुरू कर दी जिससे लाइनमैन को करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, घटना की जानकारी बिजली विभाग पेटलावद को दी गई लेकिन आधे घन्टे बाद भी कोई जवाबदार अधिकारी मौके पर नही पहुँचा जबकि विभाग का कार्यालय 2 किलोमीटर ही दूर है। देर से पहुँचे अधिकारी को जब ग्रामीणों ने लाइनमैन की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया तो कर्मचारी भड़क गए और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी और इसी को आधार बनाकर प्रकरण दर्ज करवाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि, म्रतक लाइनमैन से हमारी कोई रिश्तेदारी नही थी न ही बिजली विभाग से कोई दुश्मनी फिर भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले में अपनी लापरवाही छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को फसा दिया जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

आवास योजना के लाभ के लिए सचिव और रोजगार सहायक द्वारा की जा रही पैसों की मांग

माही की गूंज, पेटलावद

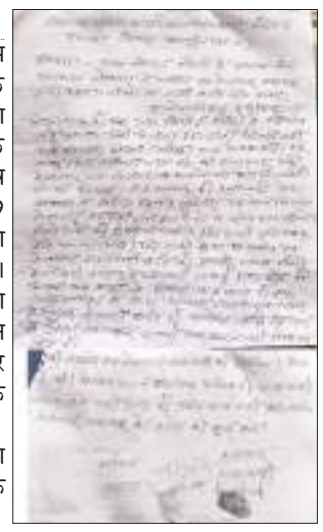

विकास खण्ड पेटलावद की ग्राम पंचायत पीठड़ी में आवास के हितग्राहियों से वसूली का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के अनुसार पंचायत सचिव और रोजगार सहायक वर्ष 2018-19 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की राशि के लिए रुपयों की मांग कर रहे हैं। आवास हितग्राही मडी बाई बैवा महिला और अत्यंत गरीब परिवार से है लेकिन ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक दोनों ने आवास की राशि के लिए बीस हजार रुपए वसूल लिए।

ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि, सचिव और सहायक सचिव लम्बे समय से ग्राम पंचायत में टिके हुए हैं एवं मनमाने ढंग से कार्य करते है, अवैध तरीके से ट्रेक्टरों की फर्जी हाजरी और बिल लगा कर राशि निकाल लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि, हम कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी आज तक बयान लेने भी नही आया, उल्टा सचिव और रोजगार सहायक दादागिरी कर लोगो को धमकाते है। मामले की शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी पेटलावद को की गई है लेकिन हर शिकायत की तरह इस शिकायत को भी साहब ने कचरे के डिब्बे का रास्ता बता दिया, जिससे अब तक कोई कार्रवाई शिकायत के बाद भी नही हो रही हैं।

फिन केयर फाइनेंस बैंक के मैनेजर व साथी के साथ लूट करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में रिमांड पर लेकर की जा रही पूछताछ

माही की गूंज, थांदला

13 अगस्त 2020 को फरियादी लखन अग्रवाल मैनेजर फिनकेयर बैंक अपने दो बैंक कर्मचारी सोनू शिंदे एवं रोहित सोलंकी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में फाइनेंस की वसूली के लिए मोटरसाइकिल पर गए थे। ग्राम परनाली, छोटी नागनवट,मोरझरी, लाटपुरा के समूह से 1 लाख 78 हजार 720 रुपए का कलेक्शन करके तीनों मोटरसाइकिल से शाम को पेटलावद की ओर आ रहे थे तभी आरोपी कल्पेश पिता जोसप डामोर, प्रियांश पिता मनसू रावत, अमित पिता रमेशचंद्र डामोर, अनिल पिता बाला सिंगारिया निवासी गोरिया खदान व अन्य साथी के साथ दो मोटरसाइकिल से पीछा करके फरियादी की मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके रोका एवं चाकू अड़ाकर उनके साथ मारपीट करके उनके पास से बैग छीन लिया और बैग में रखे नगद रुपए, टैबलेट फोन एवं बैंक के कागजात, बैग सहित लूट कर ले गए। फरियादी लखन अग्रवाल की रिपोर्ट पर थाना थांदला द्वारा अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान उक्त चारों आरोपीगण को थाना थांदला की पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करी एवं लूटी हुई नगदी सहित अन्य सामग्री जब्त करने हेतु न्यायालय में पुलिस रिमांड आवेदन न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नदीम खाने के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारोंपरांत न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया। थांदला पुलिस रिमांड मिलने के बाद आरोपियो से उक्त लूट मामले में पुछताछ कर रही है।

आगामी त्यौहारो को देखते हुए ली शांति समिति की बैठक

माही की गूंज, सारंगी संजय उपाध्याय

गणेश उत्सव, तेजा दशमी, मोहर्रम के त्योहार को देखते हुए चौकी प्रभारी उषा अलावा ने शांति समिति की बैठक सारंगी चौकी पर रखी गई, जिसमें चौकी प्रभारी ने बताया गणेश उत्सव पर भक्त अपने घरों में ही गणेश जी की स्थापना करें सार्वजनिक रूप से कहीं पर भी आयोजन नहीं होंगे, मूर्ति विसर्जन में एक ही गाड़ी में सभी मूर्तियों को ले जाकर विसर्जन करें। मोहर्रम का त्यौहार भी अपने घर पर ही मनाएं, तेजा दशमी का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंदिर पर भीड़ नहीं होने दे, कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी को देखते हुए प्रशासन के आदेश का पालन करें, व्यापारियों को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए बताया गया कि, आप स्वयं मास्क लगाएं, सैनेटाइजर का उपयोग करें और ग्राहकों से भी दूरी बनाए रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

पेटलावद को तीन माह में मिला चौथा एसडीएम

शिशिर गेमावत होगे पेटलावद के नए एसडीएम, एक-दो दिन में संभाल सकते है चार्ज

माही की गूंज, पेटलावद

प्रदेश में चल रहे अधिकारीयो के तबादले की फेरिस्टर में एक बार फिर पेटलावद अनुविभागीय अधिकारी का नाम शामिल हुआ हैं, पिछले तीन माह में पेटलावद में चौथे अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाएगा, अब तक की व्यवस्था जिले से चल रही थी, लेकिन भोपाल से जारी नए ट्रांसफर सूची के अनुसार शिशिर गेमावत ,सहायक कलेक्टर जिला रीवा से अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के रूप में भेजे गए हैं। इससे पहले पेटलावद में तीन माह में एसडीएम एमएल मालवीय, एसडीएम डॉक्टर अभय खराड़ी को वापस झाबुआ भेजा जा चुका है वर्तमान में एलएन गर्ग अनुविभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

पालने में झूले भगवान महावीर

कोरोना नियमों के तहत हुआ जन्मवाचन

माही की गूंज, रतलाम राघवेंद्र सिंह डोडिया

नगर पिपलोदा के महावीर स्वामी मंदिर पर महापर्व पर्युषण के पाचवे दिन सकल जैन श्री संघ द्वारा भगवान महावीर स्वामी का जन्मवाचन कार्यक्रम महोत्सव के रूप में मनाया। नवयुवक परिषद प्रांतीय उपाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन अनुसार पक्षाल पूजा, केशर पूजा व स्नात्र पूजा सम्पन्न हुई साथ ही भगवान महावीर स्वामी का जन्मवाचन वाटिका उपाध्यक्ष शिखर बोहरा द्वारा किया गया। श्री संघ द्वारा मन्दिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। बारी-बारी से सभी ने भगवान को पालना झुलाया। परम्परा का निर्वहन करते हुए भगवान को मंदिर के बाहर चौराहे पर जुलूस के रूप में भ्रमण करवाया गया जहाँ नगरवासियो ने भगवान महावीर स्वामी के दर्शन लाभ लिए। तत पश्चयात भगवान की आरती हुई व प्रसादी का वितरण किया गया। जन्मवाचन कार्यक्रम को लेकर भगवान का मनमोहक श्रृंगार व मन्दिर पर आकर्षक साज-सज्जा की गई। इस अवसर पर श्री संघ अध्यक्ष बाबूलाल धींग, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र कोठारी, नवयुवक अध्यक्ष महेश बोहरा, ऋषभ धींग, वाटिका ट्रस्टी मुकेश रॉयल, संजय बोहरा, मनीष जैन, नीलेश नांदेचा, नवयुवक परिषद राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रफुल्ल जैन, तरुण परिषद राष्ट्रीय महामंत्री हर्ष कटारिया, हिमांशु पटवा, सौरभ जैन आदि उपस्थित थे।

24 घंटे में 262 की नेगेटिव व 24 की आई पॉजिटिव रिपोर्ट

माही की गूंज खरगोन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा बुधवार को हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 24 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। 24 घंटे में 33 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह जिले में कुल कोरोना से संक्रमित 1190 मरीज है। इनमें 958 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए, 24 की मृत्यू तथा 208 मरीज स्थिर है। पिछले 24 घंटे में 262 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा 518 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए है। जिले में कुल 109 कंटेनमेंट एरिया घोषित है।

रतलाम कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान का तबादला, गोपाल चंद्र डाड होंगे नये कलेक्टर

रतलाम। अभी-अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार लम्बे अंतराल के बाद आज बुधवार को रतलाम कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान को अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल पदस्थ किया गया है । अब रतलाम के नवीन कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड होंगे। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है। इस बीच रतलाम कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान का स्थांतरण नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल हो चूका है। वही रतलाम के नवीन कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड को बनाया गया है।

भारतीय किसान संघ ने अपनी बैठक में लिए अहम निर्णय

माही की गूंज, सनावद

भारतीय किसान संघ द्वारा एक दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। जिसमें संगठन की रीति-नीति कार्य पद्धति को लेकर संगठन मंत्री अतुल माहेश्वरी ने मार्गदर्शन दिया एवं संगठन के आगे होने वाले कार्य बलराम जयंती मनाने का लक्ष्य दिया गया। संगठन द्वारा समस्या आने को लेकर कार्यकर्ता में आक्रोश था। वर्तमान में क्षेत्र मे मिर्ची की फसल पूरी तरह से वायरस से खराब हो चुकी है व कपास की फसल भी खराब हो रही है। जिसको लेकर अलग-अलग ग्रामो के किसानों से चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओ द्वारा गांव-गांव मे जाकर बलराम जयंती मना कर जन जागरण कर आगामी आंदोलन की तैयारी की जायेगी।

नगर के टेंट एवं लाइट डेकोरेशन के समस्त व्यापारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जेएस बघेल को दिया ज्ञापन

माही की गूंज थांदला

टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन राठौर ने बताया कि, कोविड-19 के चलते पिछले 6 माह से नगर के समस्त टेंट व लाइट डेकोरेशन के व्यवसायी का कारोबार पूर्ण रूप से बंद है इस व्यवसाय से जुड़े श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है व जिन व्यवसायी द्वारा बैंक से ऋण लिया गया था, आज वो किस्त तक जमा नही कर पा रहे है। उक्त समस्या को बताकर एसडीएम श्री बघेल को ज्ञापन देकर मांग की है कि, आपके माध्यम से शासन को ज्ञापन देकर हमारी समस्याओ अविलंब दूर कर हमें सहयोग प्रदान करने की अनुकम्पा करे। ज्ञापन देने में अर्जुन राठौड़, गोपाल वैरागी, संदीप पांचाल, जियाजी, संदीप डामोर, मोहिब खान, पंकज सोनी, मनीष नागर, विनय सहित समस्त पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

एसडीएम श्री बघेल ने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि, आप के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया वो आज ही स्थानीय प्रशासन एवं शासन को भेज दिया जावेगा। ज्ञापन का वाचन गोपाल वैरागी द्वारा किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई टाइटल कोड नंबर- एमपीएचआईएन-76422